

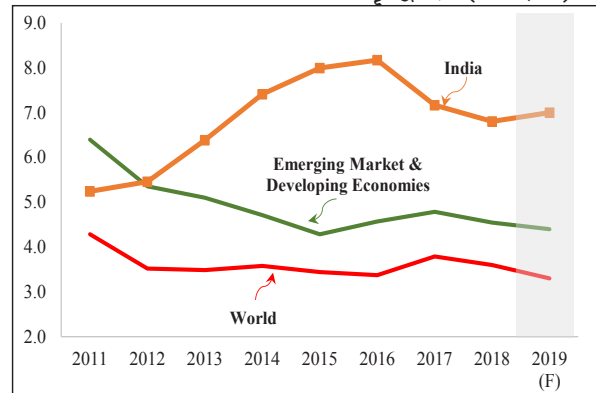
2018-19 में अर्थव्यवस्था की स्थिति : एक समष्टि परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2018 कठिनाई भरा था, इस समय विश्व की उत्पादन वृद्धि दर 2017 में 3.8 प्रतिशत से घटकर 2018 में 3.6 प्रतिशत पर आ गई। यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि विश्व उत्पादन की वृद्धि दर 2019 में और अधिक गिरकर 3.3 प्रतिशत पर आ जाएगी क्योंकि उन्नत और उभरते तथा विकासशील देशों की वृद्धि में गिरावट आने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि 2018-19 में 6.8 प्रतिशत के साथ कुछ नरम रही जो 2017-18 में 7.2 प्रतिशत से मामूली कम है। तथापि, भारत विश्व में सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। भारत, ने 4 प्रतिशत के भीतर मुद्रास्फीति को बनाए रखकर और जीडीपी के अनुपात में चालू खाता घाटा को सहनीय स्थिति में लाकर अपनी समष्टि आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा। 2017-18 की तुलना में 2018-19 में चालू खाता घाटा जीडीपी के अनुपात में अधिक था, यह मुख्यतः तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में लगभग 14 डालर प्रति बैरेल अधिक था। तथापि, वर्ष की तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटा कम होने लगा। 2018-19 में विनिर्माण के क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई थी जबकि कृषि क्षेत्र में नरमी रही। निवेश, जो बहुत वर्षों से नरम रहा और सबसे कम रहा, 2017-18 से इसमें सुधार शुरू हुआ। वस्तुतः नियत निवेश की वृद्धि दर में तेजी आई, जो 2016-17 में 8.3 प्रतिशत से 2017-18 में 9.3 प्रतिशत हुई और 2018-19 में और अधिक बढ़कर 10.0 प्रतिशत पर आ गई। निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 2018-19 में 14.2 प्रतिशत बढ़ा। केन्द्र सरकार का पूंजी व्यय 2018-19 में 15.1 प्रतिशत बढ़ा जिसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में पूंजी व्यय का हिस्सा बढ़ गया। अर्थव्यवस्था में समष्टि आर्थिक स्थिति और सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों के चलते 2019-20 में अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।

विहंगावलोकन: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

1.1 भारत 2018-19 में विश्व में सबसे तीव्र उभरती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था रही, जिसमें इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2017-18 में 7.2 से गिरकर 2018-19 में 6.8 प्रतिशत हो गया जबकि वैश्विक उत्पादन में वृद्धि 2017 में 3.8 प्रतिशत से गिरकर 2018 में 3.6 प्रतिशत पर आ गई। 2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था और उभरते बाजार तथा विकासशील देशों में मंदी संयुक्त राज्य अमरीका चीन के बीच व्यापार तनाव, चीन में कठोर ऋण नीतियों और अधिकांश उन्नत देशों में मौद्रिक नीति सामान्य होने के पश्चात आई हैं। वर्ष 2019 में, जब विश्व की अर्थव्यवस्था और ईएमडीई में क्रमशः 0.3 और

चित्र 1: वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)



आंकड़ा स्रोत: वैश्विक आर्थिक संभावना आंकड़ा आधार, अप्रैल, 2019, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत के लिए आंकड़ों हेतु केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत के लिए 2019 का पूर्वानुमान समीक्षा का पूर्वानुमान है।

तालिका: 0.1: प्रमुख संकेतक

आंकड़ा श्रेणी	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जीडीपी और संबंधित संकेतक					
वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी	₹ करोड	13771874	15362386	17095005	19010164 ^a
स्थिर बाजार कीमतों पर जीडीपी	₹ करोड	11369493	12298327	13179857	14077586 ^a
वृद्धि दर	(प्रतिशत)	8.0	8.2	7.2	6.8 ^a
स्थिर (आधार) कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित	₹ करोड	10491870	11318972	12104165	12906936 ^a
वृद्धि दर	(प्रतिशत)	8.0	7.9	6.9	6.6 ^a
सकल बचत	जीडीपी का %	31.1	30.3	30.5	NA
सकल पूंजी निर्माण	जीडीपी का %	32.1	30.9	32.3	NA
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (वर्तमान कीमतों पर)	₹	94797	104659	114958	126406 ^a
Production					
उत्पादन खाद्यान	मिलियन टन	251.5	275.1	285.0	283.4 ^b
औद्योगिक उत्पादन (वृद्धि) का सूचकांक	(प्रतिशत)	3.3	4.6	4.4	3.6
बिजली उत्पादन (वृद्धि)	(प्रतिशत)	5.6	4.7	4.0	3.5
कीमतें					
थोक कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति (औसत)	(प्रतिशत)	-3.7	1.7	3.0	4.3
उपभोक्ता कीमत सूचकांक (संयुक्त)	(प्रतिशत)	4.9	4.5	3.6	3.4
मुद्रास्फीति (औसत)					
विदेशी क्षेत्र पण्य वस्तु निर्यात वृद्धि (अमरीकी डॉलर में)	(प्रतिशत)	-15.5	5.2	10.0	8.8
पण्य वस्तु आयात वृद्धि (अमरीकी डॉलर में)	(प्रतिशत)	-15.0	0.9	21.1	10.4
चालू खाता शेष	जीडीपी का %	-1.1	-0.6	-1.9	-2.6 ^c
विदेशी मुद्रा भंडार (वर्ष अंत)	बिलियन अमरीकी डालर	360.2	370.0	424.5	412.9
औसत विनिमय दर	अमरीकी डॉलर	65.5	67.1	64.5	69.9
मुद्रा और ऋण					
स्थूल मुद्रा (एम 3) वृद्धि (वार्षिक)	(प्रतिशत)	10.1	10.1	9.2	10.5
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण (वृद्धि दर)	(प्रतिशत)	10.9	8.2	10.0	13.3
राजकोषीय सूचक (केंद्र)					
सकल राजकोषीय घाटा	जीडीपी का %	3.9	3.5	3.5	3.4 ^d
राजस्व घाटा	जीडीपी का %	2.5	2.1	2.6	2.3 ^d
प्राथमिक घाटा/जीडीपी का %	जीडीपी का %	0.7	0.4	0.4	0.3 ^d

टिप्पणियां: एनए: उपलब्ध नहीं

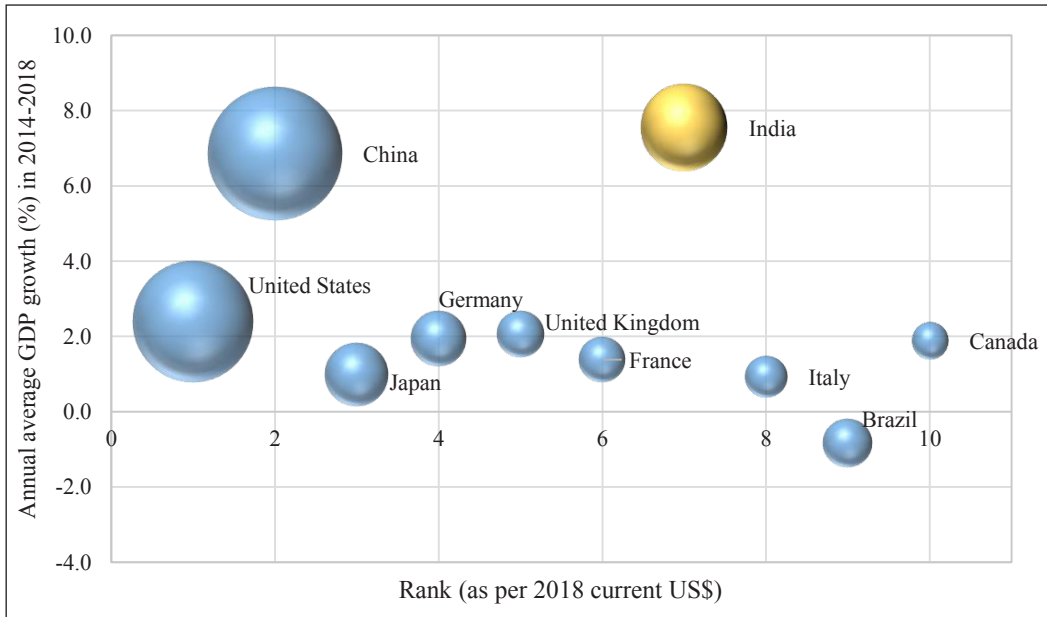
क: अंतिम अनुमान ख: तीसरा अग्रिम अनुमान ग: (अप्रैल-दिसंबर) 2018 घ: अंतिम वास्तविक

1.1 प्रतिशतांक गिरावट आना पूर्वानुमानित है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने का पूर्वानुमान है (चित्र 1) महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत उस 30 प्रतिशत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल है जिसकी संवृद्धि में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वैश्विक आर्थिक संभावना द्वारा 2019 में गिरावट आने का अनुमान नहीं लगाया गया है (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैश्विक आर्थिक संभावना, अप्रैल 2019)।

1.2 वर्तमान में अमरीकी डालर में जीडीपी के संदर्भ में भारत सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह सबसे तेज विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप

अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान लगातार बढ़ा है (चित्र 3)। एक दशक से भी कम अवधि में ईएमडीई की जीडीपी में भारत का योगदान लगभग 1.3 प्रतिशतांक बढ़ा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 0.7 प्रतिशतांक बढ़ा है। 2018 में ईएमडीई की जीडीपी में भारत का हिस्सा 8 प्रतिशत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वैश्विक आर्थिक संभावना अप्रैल 2019 के अनुसार मुख्य रूप से चीन और भारत में वृद्धि होने और वैश्विक आय में उनका भारांश बढ़ने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारत और चीन ईएमडीई समूह में वृद्धि के मुख्य संचालक हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेषकर

चित्र 2: शीर्ष दस देशों के बीच वैश्विक तुलना



आंकड़ा स्रोत: वैश्विक आर्थिक संभावना अप्रैल, 2019 आंकड़ा आधार।

टिप्पणी: फ्रांस और इटली के लिए वर्ष 2018 का डीजीपी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानित आंकड़े हैं।

गोलाई का आकार वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर के संदर्भ में डीजीपी (पीपीपी) दर्शाता है।

में उभरा है (चित्र 2)। वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान भारत की औसत वृद्धि दर न केवल चीन से अधिक है बल्कि विश्व में अन्य शीर्ष के प्रमुख देशों (वर्तमान अमरीकी डॉलर के संदर्भ में जीडीपी के अर्थ में मापित) से भी बहुत अधिक है। क्रय शक्ति की समानता के समायोजन के साथ वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में भारत की जीडीपी का स्थान विश्व में तीसरा है (जैसा कि चित्र 2 में गोलाई के आकार द्वारा दर्शाया गया है)।

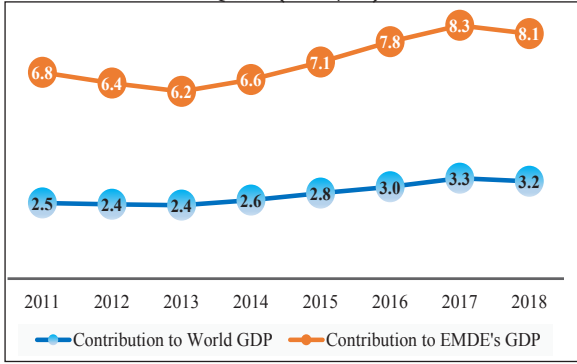
1.3 पिछले वर्षों में ईएमडीई के जीडीपी और वैश्विक

वैश्विक विकास के केंद्र के रूप में चीन न्यून स्तर पर पुनः संतुलित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की भूमिका बढ़ रही है। इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत का योगदान बहुत अधिक मूल्यवान हो गया है।

विहंगावलोकन: भारतीय अर्थव्यवस्था

1.4 पिछले 5 वर्षों (2014-15 के बाद) में 7.5 प्रतिशत औसत वृद्धि के साथ भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि उच्च रही है। 2018-19 में, भारतीय अर्थव्यवस्था

चित्र 3: ईएमडीई और विश्व की जीडीपी में भारत का हिस्सा (प्रतिशत)



आंकड़ा स्रोत: वैश्विक आर्थिक संभावना अप्रैल, 2019 आंकड़ा आधार।

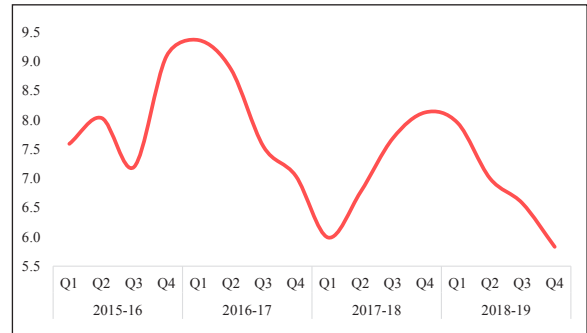
में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम है। वृद्धि की गति में यह गिरावट मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं तथा लोक प्रशासन और रक्षा के क्षेत्रों में कम वृद्धि के कारण हुई। रबी फसल के लिए 2018-19 में एकड़-वार क्षेत्रफल पिछले वर्ष की तुलना में कम था, जिससे कृषि का प्रदर्शन प्रभावित हुआ। खाद्य कीमतों में कमी आने के कारण हतोत्साहित होकर किसान कम फसल उपजाने लगे। मांग पक्ष पर 2018-19 में जीडीपी में कम वृद्धि, सरकारी अंतिम उपभोग की वृद्धि में कमी आने के कारण तथा भंडार में परिवर्तन एवं मूल्यमान कम होने के कारण हुई।

1.5 जब हम 2018-19 की विभिन्न तिमाहियों में वृद्धि में पैटर्न की जांच करते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते

गई। 2017-18 की चौथी तिमाही में 8.1 प्रतिशत की उच्च वृद्धि से उत्पन्न आरंभिक प्रभाव के कारण भी 2018-19 की चौथी तिमाही में नरमी रही। इस तिमाही में, चुनाव संबंधी अनिश्चितता का भी योगदान रहा होगा।

1.6 2018-19 की अंतिम तिमाही में 'कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कमी आई थी यद्यपि पिछली तीन तिमाहियों में समुचित वृद्धि हुई थी। उद्योग क्षेत्र की वृद्धि में भी 2018-19 की बाद की तिमाहियों में कमी देखी गई यह अधिकांशतः विनिर्माण क्षेत्र में मन्द वृद्धि के कारण हुई थी। (तालिका 1) यह विनिर्माण क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भी देखी गई जिसमें पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 7.5 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 की चौथी तिमाही में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्र ऑटो के क्षेत्र में रही मंदी के द्वारा भी प्रभावित

चित्र 4: तिमाही वास्तविक जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)



आंकड़ा स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

सारणी 1.1: सकल मूल्य वर्धन में तिमाही वार वृद्धि

	2017-18				2018-19			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	4.2	4.5	4.6	6.5	5.1	4.9	2.8	-0.1
उद्योग	0.8	6.9	8.0	8.1	9.8	6.7	7.0	4.2
(जिसमें से) विनिर्माण	-1.7	7.1	8.6	9.5	12.1	6.9	6.4	3.1
सेवाएं	9.4	6.8	8.0	8.2	7.1	7.3	7.2	8.4
आधार कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन	5.9	6.6	7.3	7.9	7.7	6.9	6.3	5.7
बाजार कीमतों पर डीजीपी	6.0	6.8	7.7	8.1	8.0	7.0	6.6	5.8

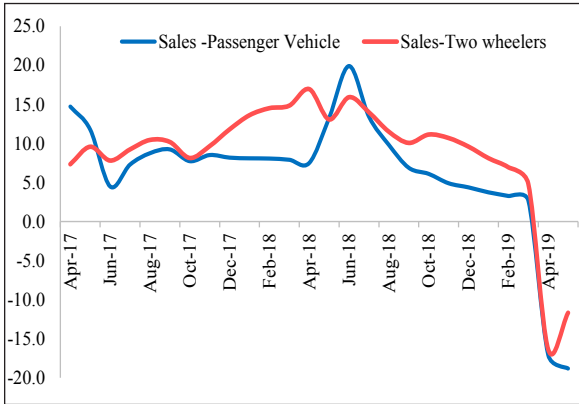
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

हैं कि 2018-19 की सभी तिमाहियों में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि में नरमी देखी गई है। (चित्र 4) इसकी चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की

हुआ, जहां वाणिज्यिक वाहनों के अलावा सभी क्षेत्रों के लिए उत्पादन वृद्धि 2017-18 की तुलना में 2018-19 में गिरी है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बहुत सी श्रेणियों में

बिक्री की वृद्धि में मन्दी आई, जिनमें सवारी वाहन, ट्रैक्टर की बिक्री, तिपहिए और दुपहिए की बिक्री शामिल है (चित्र 5)। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के क्षेत्र में दबाव ने भी उपभोग वित्त को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके मन्दी में योगदान दिया (चित्र 6)। 2018-19 के भीतर विनिर्माण की वृद्धि में नरमी के बावजूद वर्ष में समग्र वृद्धि, 2018-19 की पहली तिमाही में 12.1 प्रतिशत वृद्धि होने की वजह से 2017-18 की तुलना में अधिक हुई थी।

चित्र 5: सवारी वाहनों और दुपहियों की संचयी बिक्री (संख्या) में परिवर्तन (प्रतिशत)



आंकड़ा स्रोत: एसआईएम

टिप्पणी: अप्रैल से वर्ष के संबंधित महीने, से वृद्धि दर संचयी बिक्री के लिए हैं।

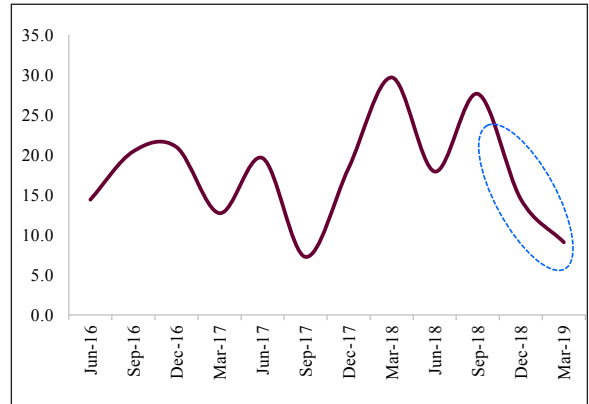
1.7 मांग पक्ष से 2018-19 के दौरान जीडीपी की वृद्धि में गिरावट अंतिम दो तिमाहियों में निजी अंतिम उपभोग में कमी के कारण आई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से कम आय की वजह से हुई, इसका कारण खाद्य की कम कीमत और एनबीएफसी में दबाव के कारण भी हुई जिसने इसके द्वारा प्रदत्त ऋणों को प्रभावित किया था। 2018-19 की चौथी तिमाही में भी वैश्विक उत्पादन वृद्धि कम होने के कारण निर्यात में वृद्धि कम हुई।

1.8 यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर अधिक थी, इसी दौरान 2010-11 के बाद से नामिक, जीडीपी वृद्धि में मामूली गिरावट आई। यह मुद्रास्फीति में निरंतर कमी का परिचालक है, जैसाकि चित्र 7 में देखा जा सकता है, वास्तविक और नामिक वृद्धि दर के बीच अंतर काफी कम हुआ है, जिससे

जीडीपी अपस्फायक कम हो गया है। जीडीपी अपस्फायक उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक का भाराशित औसत है।

1.9 इसे पिछले कुछ वर्षों के दौरान उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट में दर्शित हुआ है (चित्र 8)। 2013-14 में, उपभोक्ता कीमत सूचकांक हेडलाइन मुद्रास्फीति द्विअंकीय के आस-पास थी परंतु, इसके बाद यह धीरे-धीरे गिरकर 4 ((/-) 2) प्रतिशत के दायरा के लक्ष्य के भीतर रही है। हेडलाइन सीपीआई 2017-18 में 3.6 प्रतिशत से गिरकर 2018-19 में 3.4

चित्र 6: एनबीएफसी के ऋणों और अग्रिमों की वर्षानुवर्ष वृद्धि (प्रतिशत)



आंकड़ा स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी: जमा प्राप्त करने वाले एनबीएफसी और जमा प्राप्त न करने वाले नियमित एनबीएफसी जिनमें सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं, से संबंधित ऋणों और अग्रिमों के आंकड़े।

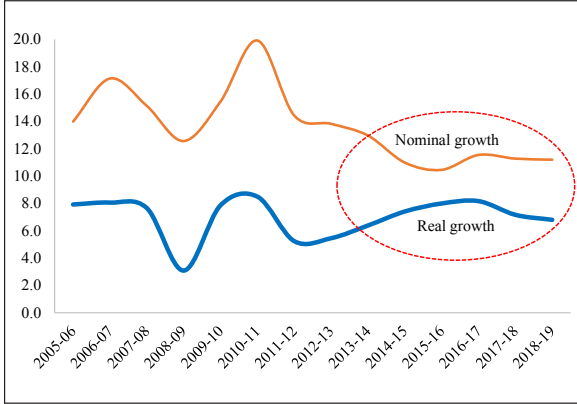
प्रतिशत पर आ गई।

1.10 हेडलाइन थोक कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति 2018-19 में 4.3 प्रतिशत थी, जो 2017-18 में 3.0 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी। थोक कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति में वृद्धि का आधार व्यापक है, जिसमें, 2018-19 में खाद्य को छोड़कर सभी समूहों की मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी देखी गई। थोक कीमत सूचकांक में वृद्धि के परिणामस्वरूप जीडीपी अपस्फायक में मामूली तेजी आई, जो 2017-18 में 3.8 प्रतिशत से 2018-19 में 4.1 प्रतिशत हो गई।

1.11 प्रमुख सकल मूल्य में वृद्धि (कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों और लोक प्रशासन एवं रक्षा के बगैर जीवीए के रूप में मापा जाने वाला) 2018-19 में समग्र वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि दर्शाती है। प्रमुख जीवीए

वृद्धि 2017-18 में 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 7.0 प्रतिशत हो गई, जबकि जीवीए में वृद्धि 2017-18 में 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 6.6 प्रतिशत

चित्र 7: जीडीपी में वृद्धि (प्रतिशत)



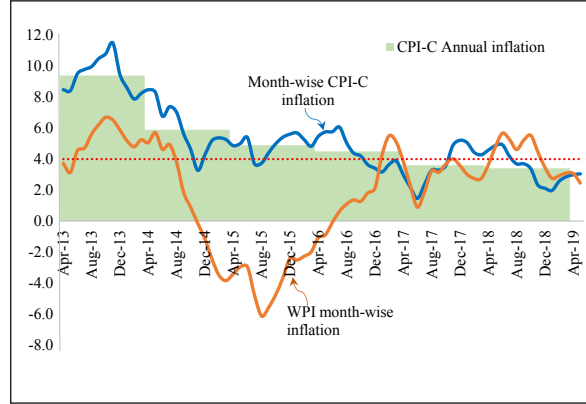
आंकड़ा स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

हो पाई। 2018-19 की सभी तिमाहियों के लिए प्रमुख जीवीए में वृद्धि समग्र जीवीए वृद्धि से अधिक थी क्योंकि कृषि और सम्बद्ध और लोक प्रशासन एवं रक्षा में अन्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत वृद्धि दर में सबसे अधिक गिरावट आई। मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र में नरमी के कारण 2018-19 की चौथी तिमाही में प्रमुख जीवीए की वृद्धि दर में पिछली तिमाही की तुलना में 1 प्रतिशतांक की गिरावट आई (चित्र 9)।

1.12 विदेशी मोर्चे पर, चालू खाता घाटा 2017-18 में जीडीपी के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर

2018 में 2.6 प्रतिशत पर आ गया (चित्र 11 देखें)। चालू खाता घाटा बढ़ने का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल (भारतीय समूह) की कीमतों में वृद्धि रहा।

चित्र 8: मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण नरमी

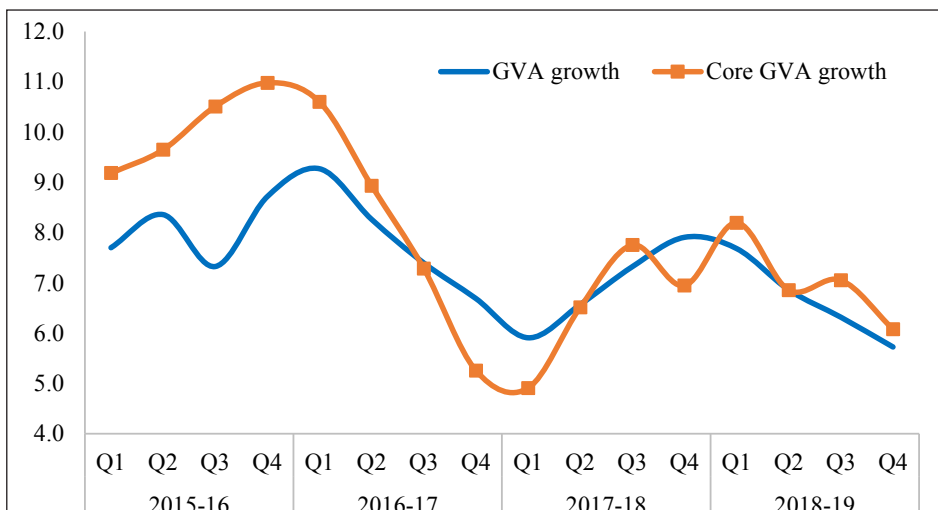


महीनावार थोक कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति टिप्पणी: सीपीआई-सी-सीपीआई समिश्र के लिए है।

व्यापार घाटा 2017-18 में 162.1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 184 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गया।

1.13 पण्य वस्तु निर्यात और आयात में हुई मामूली वृद्धि 2018-19 में अमरीकी डालर के संदर्भ में, 2017-18 की तुलना में कम हुई। किंतु पण्य वस्तु आयात बहुत तेजी से गिरा जो 21.1 प्रतिशत से घटकर 10.4 प्रतिशत पर आ गया। स्वर्ण आयात का मूल्य घटने और तेल-भिन्न, स्वर्ण-भिन्न आयातों के मूल्य में कम वृद्धि के कारण तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से तेल के निर्यात में वृद्धि

चित्र 9: वास्तविक जीवीए और वास्तविक प्रमुख जीवीए वृद्धि (प्रतिशत)



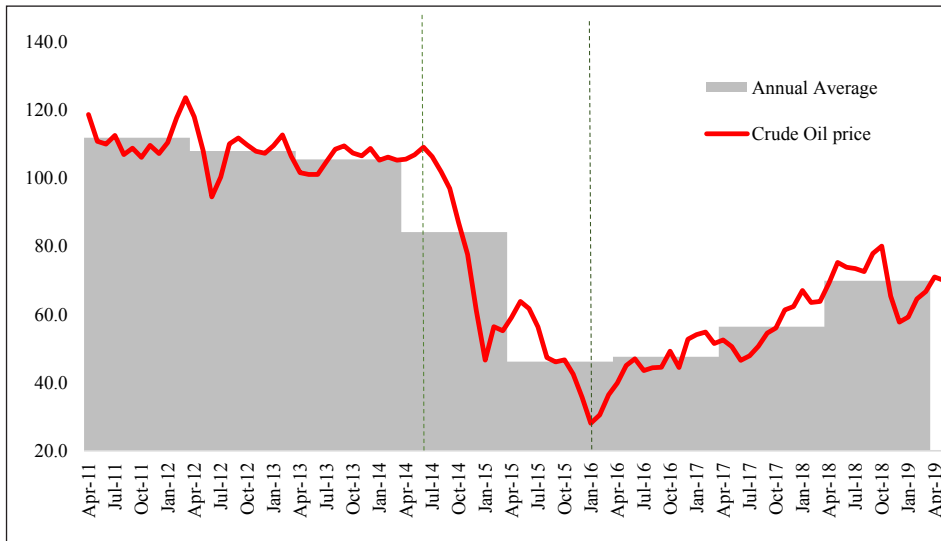
आंकड़ा स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

होने के बावजूद पण्य वस्तुओं के आयात वृद्धि में नरमी रही। किन्तु, कच्चे तेल की कीमतें, वर्ष भर घटती-बढ़ती रहीं। जैसे ही वर्ष शुरू हुआ कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं और अक्टूबर, 2018 में यह प्रति बैरल 80 अमरीकी डालर से ऊपर पहुंच गई। इसके बाद, दिसंबर 2018 के बाद दोबारा बढ़ने के पहले इसमें गिरावट आनी शुरू हुई (चित्र 10)। पिछले वर्ष की तुलना में, कुल मिलाकर, तेल की कीमतें 2018-19 में काफी अधिक थीं।

1.14 अमरीकी डालर के संदर्भ में, सेवा निर्यात और आयात में वृद्धि 2018-19 में कम हुई। 2018-19 में क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत कम हुई थी

संबंधी चिंताओं के कारण वर्ष की पहली छमाही में रुपए का अवमूल्यन हुआ। तथापि, कुछ अन्य प्रमुख उभरते बाजार की मुद्रा की तुलना में रुपए का प्रदर्शन बेहतर रहा जैसाकि अर्जेंटिना का पेसो, तुर्की का लीरा, ब्राजीली रीयल और रूसी रूबल, जिनका अमरीकी डालर की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक मूल्यहास हुआ। अमरीकी डालर के साथ न केवल द्विपक्षीय विनिमय दर के संदर्भ में, अपितु 2018-19 में व्यापार आधारित भारांशित विनिमय दर के रूप में मापने पर भी रुपए का अवमूल्यन हुआ। नामिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) (द्विपक्षीय 36 मुद्रा व्यापार आधारित भारांश) में 2018-19 में रुपए

चित्र 10: कच्चे तेल की कीमत (प्रति बैरल अमरीकी डालर में भारतीय समूह)



आंकड़ा स्रोत: पीपीएसी

जबकि 2017-18 में ये क्रमशः 18.8 प्रतिशत और 22.6 प्रतिशत रही थी।

1.15 2018-19 में रुपए का मूल्यहास अमरीकी डालर की तुलना में 7.8 प्रतिशत, येन की तुलना में 7.7 प्रतिशत और यूरो और स्टर्लिन पाउण्ड की तुलना में 6.8 प्रतिशत हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के व्यापार में मूल्यहास की प्रवृत्ति रही और 29 मार्च, 2019 को प्रति अमरीकी डालर 4.1 प्रतिशत से 69.2 प्रतिशत तक सुधरने के पहले अक्टूबर 2018 में यह 74.4 रुपये प्रति डालर पर पहुंच गया था। अमरीकी फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के फलस्वरूप संयुक्त राज्य में वित्तीय स्थिति में तंगी और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से चालू खाता घाटा बढ़ने

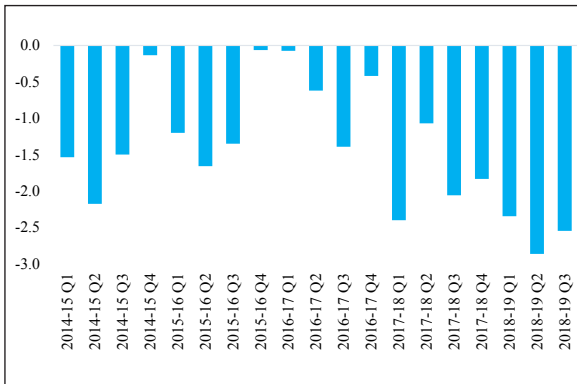
का 5.6 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ। इसी प्रकार वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में भी 2018-19 में 4.8 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ था (चित्र 12)।

1.16 नामिक (मूल्यनिर्धारण प्रभाव सहित) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार मार्च अंत 2018 की तुलना में मार्च अंत 2019 में 11.6 बिलियन अमरीकी डालर घटा। वर्ष के भीतर विनिमय दर में हास और अस्थिरता रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण अक्टूबर, 2018 तक विदेशी मुद्रा भण्डार घट रहा था, भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 14 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार सुखद 422.2 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया (चित्र 13)।

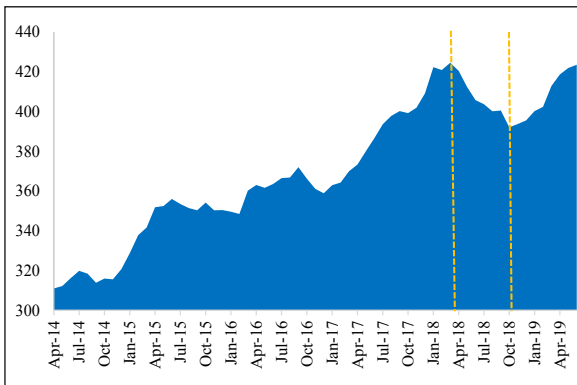
1.17 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 2018-19 में 14.2 प्रतिशत बढ़ा। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्रों में सेवाएं, ऑटोमोबाइल और रसायन थे। 2015-16 से एफडीआई अंतर्वाह में उच्च दर से वृद्धि हुई है (चित्र 14)। यह तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

1.18 2018-19 के लिए अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत था। 2018-19 में निगम कर में अच्छे प्रदर्शन की वजह से प्रत्यक्ष करों में 13.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। तथापि, माल एवं सेवा कर राजस्व (सीजीएसटी आईजीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर सहित) बजट अनुमान से लगभग 22 प्रतिशत कम होने की वजह से अप्रत्यक्ष कर लगभग 16 प्रतिशत कम रहा। माल एवं सेवा कर जुलाई, 2017 में लागू किया गया था। माल एवं सेवा कार्य लागू होने के

चित्र 11: चालू खाता शेष (जीडीपी का प्रतिशत)



चित्र 13: विदेशी मुद्रा भण्डार (बिलियन अमरीकी डालर)



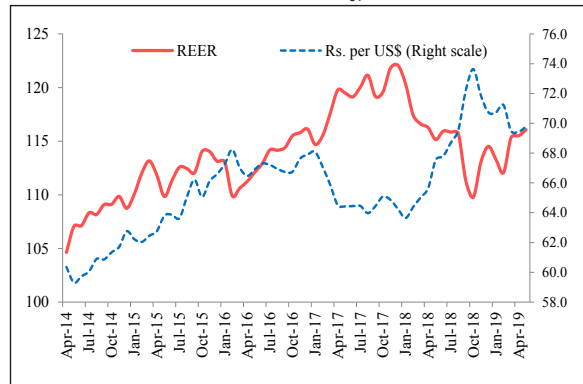
आंकड़ा स्रोत: 11 से 14 तक के आंकड़े, भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी: 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन-मई 2019 में प्रकाशित सूचना के आधार पर परिकल्पित होता है।

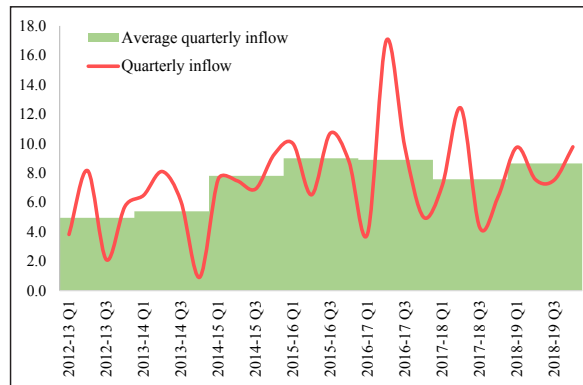
1.19 पूंजी व्यय में 15.1 प्रतिशत वृद्धि होने की वजह से 2018-19 अ.वा. में केन्द्र सरकार का कुल व्यय 7.9 प्रतिशत बढ़ा जिसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में पूंजी व्यय का हिस्सा बढ़ गया (चित्र 16)। 2017-18 में कुल व्यय में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और पूंजी व्यय में तो यह (-)7.5 प्रतिशत, अर्थात कमी रही थी।

1.20 वर्ष 2018-19 में सरकार अपने राजकोषीय समेकन के पथ पर बनी रही। 2018-19 में नया लक्ष्य ढांचा अपनाया गया था, जो ऋण और राजकोषीय घाटा कम करने के दोहरे स्तम्भ पर आधारित है। राजस्व व्यय का समेकन हुआ और 2018-19 में पूंजी व्यय की ओर धीरे-धीरे झुकाव आने से केन्द्र सरकार के व्यय की गुणवत्ता में सुधार आया। प्राथमिक और राजकोषीय घाटे में प्रगामी कमी आयी। केन्द्रीय सरकार का प्राथमिक घाटा (वह राशि जिसके द्वारा सरकार ने अपने कुल राजस्व

चित्र 12: आरईईआर और रुपया/अमरीकी डालर विनिमय दर का सूचकांक



चित्र 14: निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह (बिलियन अमरीकी डालर)



1.21 सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 2016-17 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत से घटकर 2017-18 (सं.अ.) में 3.0 प्रतिशत रह गया है और 2018-19 में इसके घटकर 2.6 प्रतिशत पर आने का बजट अनुमान किया गया है (भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार)। सामान्य सरकार, (केन्द्र और राज्यों) की संयुक्त देनदारियां मार्च अंत 2018 में घटकर 67 प्रतिशत पर आ गई है। सामान्य सराकर का राजकोषीय घाटा 2017-18 (सं.अ.) में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत से और अधिक गिरकर 2018-19 ब.अ. में जीडीपी के 5.8 प्रतिशत पर आने की आशा है।

1.22 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र दोहरे तुलन पत्र की समस्या से जूझता आ रहा है, जिन्हें दबावग्रस्त कारपोरेट एवं बैंक तुलन पत्र कहा जाता है। बैंकों की अनर्जक परिसंपदाओं में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बैंकों के तुलनपत्र पर दबाव बढ़ा। यह दबाव सरकारी बैंकों को अधिक झेलना पड़ता है। तथापि, बैंकिंग क्षेत्र (घरेलू प्रचालन) और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन विशेषकर 2018-19 में सुधरा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक परिसंपदाएं मार्च 2018 और दिसंबर 2018 के बीच 11.5 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत पर आ गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह गिरावट अधिक तेजी से आई और इसी अवधि के दौरान यह 15.5 प्रतिशत से घटकर 13.9 प्रतिशत पर आ गई।

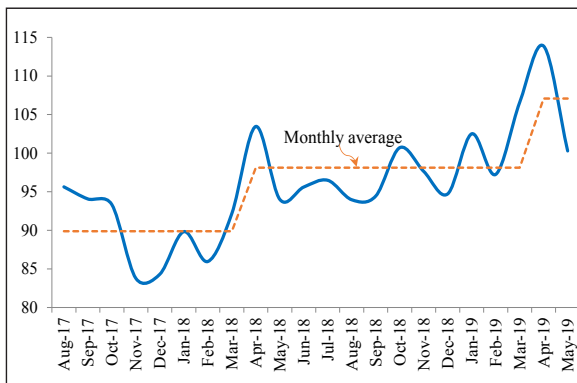
1.23 वर्ष 2018-19 के दौरान, 10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) पर प्रतिप्राप्ति अस्थिर थी (चित्र 18) और तेल की कीमतों और आंतरिक तरलता तथा रुपये की विनिमय दर में घट-बढ़ पर कड़ी नजर

हुई, जो 2018-19 की दूसरी छमाही में अपेक्षाकृत कम बाजार उधारों की आशा के साथ रुपये की अस्थिरता को थामने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों को प्रतिबिंबित करती है। 2018-19 की तीसरी तिमाही में, कच्चे तेल की कीमतों और उपभोक्ता कीमत सूचकांक की मुद्रास्फीति दरों में गिरावट के साथ-साथ, 1.36 लाख करोड़ रुपये के ओएमओ क्रयों के कारण यह प्रतिप्राप्ति आमतौर पर कम रही। फरवरी, अप्रैल और जून, 2019 में मौद्रिक नीति समिति द्वारा घोषित नीति दर कटौती के परिणामस्वरूप, इस में और कमी आई। दिनांक 10 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति से प्रतिप्राप्ति गिरकर 6.97 प्रतिशत रह गई।

वृद्धि के वाहक

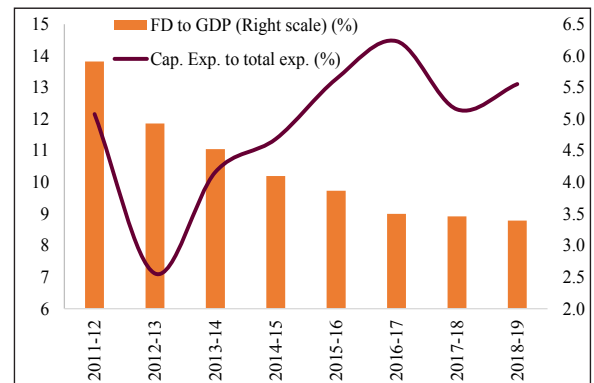
1.24 उपभोग हमेशा से ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि का एक सुदृढ़ एवं प्रमुख वाहक रहा है। कुल अंतिम उपभोग में, निजी उपभोग व्यय होता है जिसका अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख भाग है (तकरीबन 60 प्रतिशत) और इसकी वृद्धि दर अधिकतर समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से ज्यादा रहती है (तालिका 11.2)। अर्थव्यवस्था का अत्यधिक बड़ा आकार कारोबार के लिए एक बड़े बाजार के रूप में काम करता है। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) 2018-19 में 8.1 प्रतिशत बढ़ गया, यद्यपि उसी वर्ष की आखिरी दो तिमाहियों में वृद्धि की गति मंद पड़ गई। यद्यपि जीडीपी में निजी उपभोग का भाग अधिक ही रहा, समय के साथ-साथ उपभोग के पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ-आवश्यक वस्तुओं से लेकर विलासी वस्तुओं तक तथा माल से लेकर सेवाओं तक (बॉक्स 1)।

चित्र 15: जीएसटी राजस्व संग्रहण (करोड़ रुपये)



आंकड़ा स्रोत: महालेखा नियंत्रक।

चित्र 16: केन्द्रीय सरकार का व्यय (करोड़ रुपये में)

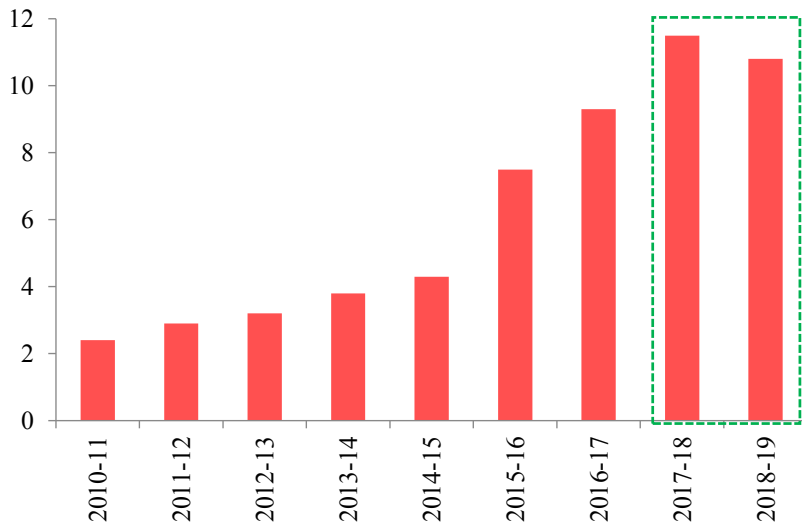


आंकड़ा स्रोत: महालेखा नियंत्रक।

होता है, जिसके भीतर अचल निवेश (सकल अचल पूंजी निर्माण) जीडीपी का लगभग 29 प्रतिशत होता है। निवेश के अन्य दो संघटक स्टॉक में परिवर्तन तथा मूल्यवान वस्तुएं होते हैं, जिनका प्रत्येक का हिस्सा लगभग जीडीपी का 1 प्रतिशत होता है। अचल निवेश का आशय मुख्य रूप से नई मशीनरी और उपकरणों का मूल्य तथा घरों और अन्य संरचनाओं के नए निर्माण

1.26 मांग का तीसरा प्रमुख घटक निवेश है। निवेश (सकल पूंजी विन्यास) जीडीपी का लगभग 32 प्रतिशत होता है, जिसके भीतर नियत निवेश (सकल नियत पूंजी विन्यास) जीडीपी का लगभग 29 प्रतिशत होता है। निवेश के अन्य दो संघटक स्टॉक में परिवर्तन तथा मूल्यवान वस्तुएं होते हैं, जिनका प्रत्येक का हिस्सा लगभग जीडीपी का 1 प्रतिशत होता है। नियत निवेश का आशय मुख्य

चित्र 17: सकल अग्रिम राशि की प्रतिशतता के रूप में अनर्जक परिसंपत्तियां



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

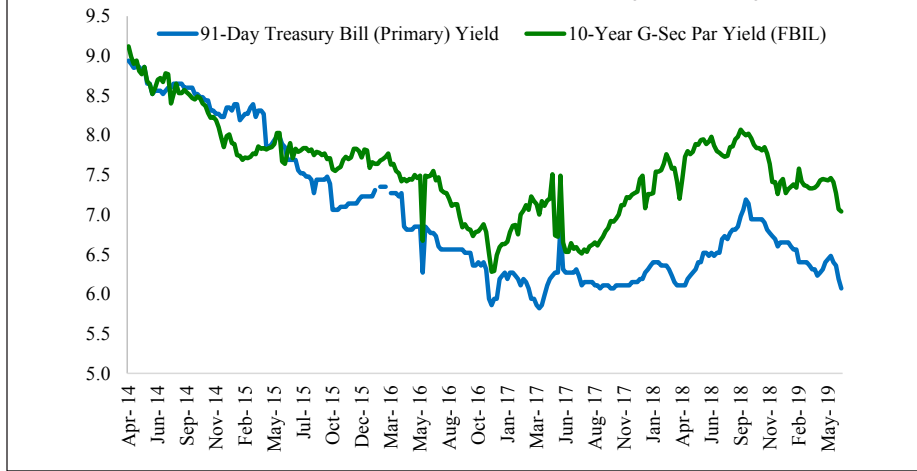
कार्यों का मूल्य होता है। सृजित जैविक संसाधन तथा बौद्धिक संपदा उत्पाद अचल निवेश के अन्य दो घटक होते हैं, हालांकि उनका अंश बहुत थोड़ा होता है।

1.25 खपत का दूसरा संघटक सरकारी अंतिम खपत व्यय (जीएफसीई) है। जीएफसीई की वृद्धि 2017-18 में 15.0 प्रतिशत से 2018-19 में कम होकर 9.2 प्रतिशत रह गई है। जीएफसीई का परिकलन ब्याज भुगतानों को घटाकर राजस्व व्यय की वृद्धि का उपयोग करके किया जाता है। जीएफसीई में कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति माल और सेवाओं की निवल खरीद तथा नियत पूंजी की खपत पर सरकारी (राजस्व) व्यय शामिल होता है। जीएफसीई में यह अपेक्षाकृत कम वृद्धि 2018-19 में सरकार की अपेक्षाकृत कम राजस्व व्यय वृद्धि के समान लगातार हुई है। औसतन, पिछले 5 वर्षों में जीएफसीई की वार्षिक वृद्धि 9.0 प्रतिशत हुई है।

रूप से नई मशीनरी और उपकरण का मूल्य तथा घरों और अन्य संरचनाओं के नए निर्माण कार्यों का मूल्य से हाता है। जोते हुए जैविक संसाधन तथा बौद्धिक संपदा उत्पाद नियत निवेश के अन्य दो घटक होते हैं, हालांकि उनका भाग बहुत थोड़ा होता है।

1.27 निवेश दर और अचल निवेश, दोनों ही में 2011-12 से दीर्घकालिक गिरावट हुई थी, जिससे प्रतीत होता है कि 2017-18 से पुनः बहाली के जो आरंभिक संकेत मिले थे, वे गायब हो गए हैं (चित्र 19)। अचल निवेश वृद्धि ने 2016-17 में 8.3 प्रतिशत से रफ्तार पकड़ी और 2017-18 में यह 9.3 प्रतिशत हो गई तथा 2018-19 में 10.0 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2016-17 तक अचल निवेश में गिरावट मुख्य रूप से परिवार सेक्टर द्वारा दर्ज की गई, जहां सरकारी सेक्टर और निजी कॉर्पोरेट सेक्टर में अचल निवेश लगभग एक ही स्तर पर बना रहा (चित्र 20)। यहां 'परिवार' सेक्टर में 'अर्ध कॉर्पोरेट'

चित्र 18: 10 वर्षीय और 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों से हुई प्रति प्राप्ति



आंकड़ा स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

भी शामिल है। घरेलू से संबंधित कॉर्पोरेट से इतर उद्यम, जिनके पास खातों के संपूर्ण सेट होते हैं, उन्हें अर्ध कॉर्पोरेट कहा जाता है। परिवार सेक्टर अधिकांशतः घरों तथा अन्य संरचनाओं में निवेश करता है जबकि अर्ध कॉर्पोरेट मशीनरी और उपकरणों में निवेश करते हैं। परिवार सेक्टर के अचल निवेश में यह गिरावट घरों में कम निवेश किए जाने के कारण हुई है। इस गिरावट का अन्य कारण परिवार सेक्टर की वास्तविक बचत में गिरावट आना भी है।

1.28 ऐसा लगता है कि निवेश कार्यकलापों में सकारात्मक स्थिति बन रही है और उद्योग के लिए ऋण वृद्धि में तेजी भी देखी जा सकती है। बड़े तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, दोनों में ऋण में वृद्धि में तेजी देखी गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंक ऋण की वृद्धि वर्ष 2016 तथा 2017 में कम हो रही थी, लेकिन वर्ष 2018 में इसने गति पकड़ना आरंभ कर दिया है। बड़े उद्योगों को ऋण वृद्धि मार्च 2016 में कम होनी शुरू हो गई थी और अक्टूबर, 2016 तक यह वृद्धि ऋणात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। 2017-2018 के आरंभ

तालिका 2: कुल मांग के घटक

घटक	वास्तविक वृद्धि (प्रतिशत)			वर्तमान कीमतों पर भाग (प्रतिशत)		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
कुल उपभोग	7.8	8.6	8.3	69.6	70.0	70.6
सरकारी उपभोग	5.8	15.0	9.2	10.3	11.0	11.2
निजी उपभोग	8.2	7.4	8.1	59.3	59.0	59.4
अचल पूंजी निवेश	8.3	9.3	10.0	28.2	28.6	29.3
भण्डार में परिवर्तन	-48.2	21.2	4.8	0.9	1.0	1.0
मूल्यवान वस्तुएं	-18.9	27.4	-9.0	1.1	1.3	1.0
माल एवं सेवाओं का निर्यात	5.1	4.7	12.5	19.2	18.8	19.7
माल एवं सेवाओं का आयात	4.4	17.6	15.4	21.0	22.0	23.6
बाज़ार कीमतों पर जीडीपी	8.2	7.2	6.8	100	100	100

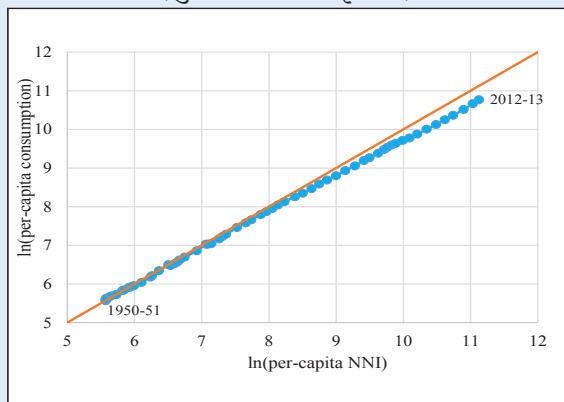
स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

टिप्पण: 2018-19 के आंकड़े अनंतिम अनुमान के अनुसार हैं।

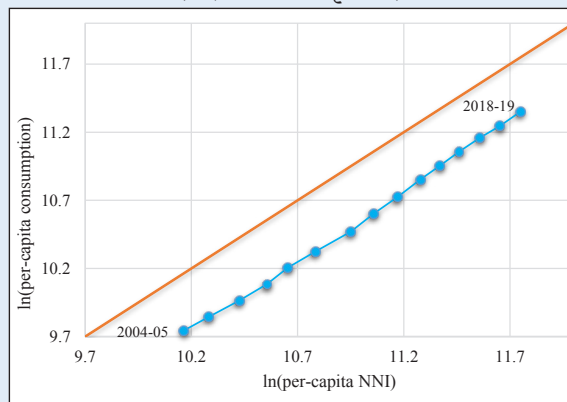
बॉक्स 1: भारत की उपभोग संबंधी उच्च आय लोचशीलता और समय के दौरान इसके बदलते प्रतिमान

प्रति व्यक्ति उपभोग और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के बीच संबंध खपत की बहुत अधिक लोचशीलता को दर्शाता है, जिसका अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति उपभोग की वृद्धि की दर लगभग उतनी ही है जितनी प्रति व्यक्ति आय की है। हो सकता है कि समय के साथ-साथ उपभोग की लोचशीलता कुछ कम हुई हो, पर फिर भी यह बहुत अधिक रही है। तालिका 'क' दर्शाती है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति पीएफसीई की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अथवा प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) की अपेक्षा थोड़ी अधिक है।

चित्र क: उपभोग की आय लोचशीलता (पुरानी जीडीपी श्रृंखला)



चित्र ख: उपभोग की आय लोचशीलता (नई जीडीपी श्रृंखला)



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

टिप्पण: पुरानी जीडीपी श्रृंखला का आशय 2004-05 आधार पर श्रृंखला से है तथा नई जीडीपी श्रृंखला का आशय 2011-12 आधार पर श्रृंखला से है।

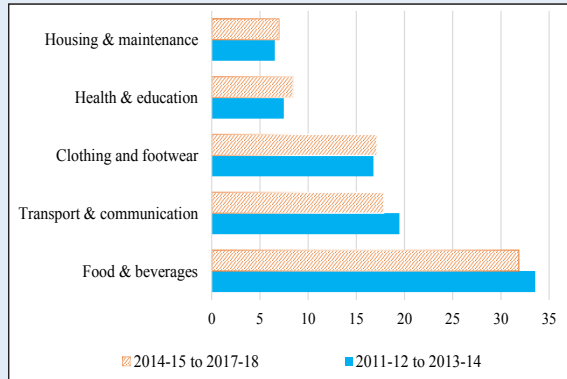
तालिका 'क': प्रति व्यक्ति आय और उपभोग का स्तर और वृद्धि

	स्तर रुपये में				वास्तविक वृद्धि (प्रतिशत में)	
	अंकित		वास्तविक		2017-18	2018-19
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
प्रति व्यक्ति जीडीपी	129901	142719	100151	105688	5.8	5.5
प्रति व्यक्ति एनएनआई	114958	126406	87623	92565	5.7	5.6
प्रति व्यक्ति पीएफसीई	76619	84760	56364	60185	6.0	6.8

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

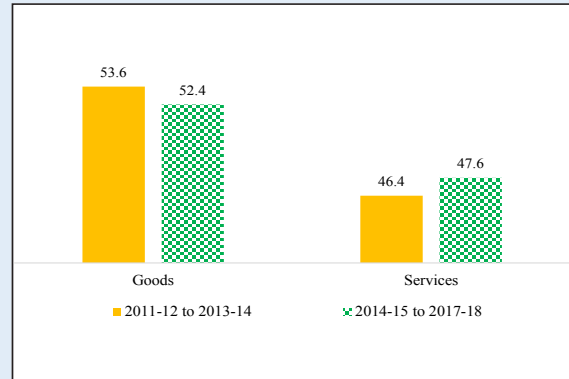
यद्यपि उपभोग की लोचशीलता बहुत अधिक रही, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में इसकी संरचना में बदलाव हुआ है। खाद्य एवं पेय पदार्थ, परिवहन एवं संचार जो अधिकतर आवश्यकता हुआ करती है, से खर्च करने की प्रवृत्ति बदल कर परिधान एवं जूते, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, आवासन एवं अनुरक्षण की ओर अंतरित हो गई है (चित्र ग)। यह दर्शाता है कि परिवारों द्वारा अब आवश्यकताओं की तुलना में विवेकाधीन व्यय कहीं अधिक किया जा रहा है। यह रूपान्तरण खर्च के प्रतिमान में भी इस प्रकार देखा जा सकता है कि वस्तुओं के उपभोग पर किया जाने वाला खर्च अब सेवाओं के उपभोग हेतु किया जा रहा है। कुल अंतिम उपभोग में वस्तुओं के भाग में गिरावट हुई है, जिससे सेवाओं के भाग में 1 प्रतिशतता बिन्दु से अधिक की तदनुसूची वृद्धि हुई है (चित्र घ)।

चित्र ग: प्रमुख प्रयोजनों में उपभोग व्यय का भाग (प्रतिशत)



स्रोत: घरेलू खपत व्यय पर एनएसएसओ रिपोर्ट।

चित्र घ: उपभोग के अंश में परिवर्तन (प्रतिशत)



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा घरेलू उपभोग सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि समय के साथ-साथ कुल उपभोग में खाद्य पदार्थों से इतर व्यय के अंश में बढ़ोत्तरी हुई है। ध्यान देने की पहली रोचक बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कुल उपभोग में खाद्य पदार्थों का भाग 10 प्रतिशतांक से अधिक कम है। दूसरे यह कि कुल उपभोग में खाद्य पदार्थों का भाग 1999-2000 से 2011-12 तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6.5 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 5.5 प्रतिशत कम हुआ है। खाद्य पदार्थों में ही, लगभग पूरी की पूरी गिरावट खाद्यान्न में देखी गई है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में 1999-2000 से 2011-12 के बीच खाद्यान्न का भाग घटकर आधा रह गया। समग्र रूप से, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात और टिकाऊ माल के लिए व्यय के बढ़ते हुए भाग के साथ खाद्य पदार्थों से इतर व्यय के भाग में बढ़ोत्तरी हुई है (तालिका 'ख')। यह दर्शाता है कि समय के साथ आवश्यक वस्तुओं पर व्यय धीरे-धीरे कम होता गया है और विवेकाधीन व्यय की ओर बढ़ता गया है। वर्ष 2011-12 में भी, 1999-2000 की भांति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों से इतर व्यय का भाग लगभग 10 प्रतिशतांक अधिक है। शिक्षा पर व्यय का भाग 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में लगभग दोगुना है (तालिका 'ख')।

तालिका ख: कुल (प्रतिशत) में मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय का भाग

	ग्रामीण			शहरी		
	1999-00	2004-05	2011-12	1999-00	2004-05	2011-12
खाद्य पदार्थ (जिसमें से)	59.4	55.1	52.9	48.1	42.5	42.6
खाद्यान्न	22.2	18.1	10.8	12.3	10.1	6.7
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	8.8	8.4	8.0	8.7	7.9	7.0
सब्जियां	6.2	6.1	6.6	5.1	4.5	4.6
खाद्य पदार्थ से इतर (जिसमें से)	40.6	44.9	47.1	51.9	57.5	57.4
परिधान एवं जूते	8.0	5.4	7.0	7.2	4.7	6.3
शिक्षा	1.9	2.7	3.5	4.3	5.0	6.9
चिकित्सा	6.1	6.6	6.6	5.1	5.2	5.6
परिवहन	2.9	3.8	4.2	5.5	6.6	6.5
टिकाऊ माल	2.6	3.4	4.5	3.6	4.1	5.3

स्रोत: घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ रिपोर्ट

में यह बहाल होनी शुरू हुई, लेकिन गति 2018 की दूसरी छमाही में ही तेज हुई है (चित्र 21)।

1.29 क्षेत्रीय स्तर पर 2011-12 से निवेश दरें कम होती आ रही हैं यद्यपि सेवाओं में निवेश दर गिरावट के तल को पार कर पुनः उन्नयन के लक्षण दर्शा रही है। वर्ष 2011-12 में उद्योग सेक्टर में निवेश दर उच्चतम थी, जिसके बाद सबसे ज्यादा निवेश सेवा सेक्टर में हुआ जबकि सेवा सेक्टर में जितना निवेश हुआ उसकी तुलना में कृषि सेक्टर में निवेश आधे से भी काफी कम रहा। 2017-18 में सेवा सेक्टर में निवेश की दर अधिकतम हो गई। कृषि में निवेश दर निरंतर पिछड़ती रही और अब यह उद्योग सेक्टर में निवेश की दर से आधी है।

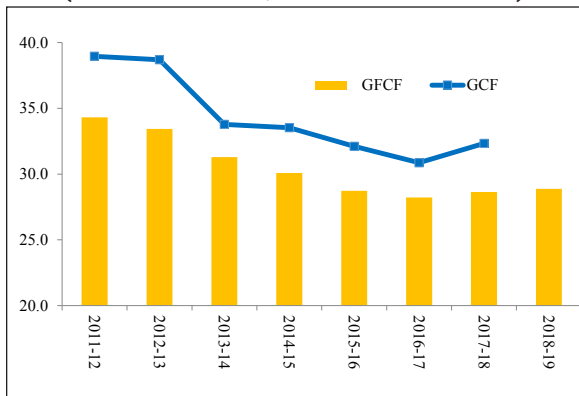
1.30 साथ ही साथ, बचत दर में भी गिरावट हुई है जिसका कारण संपूर्ण रूप से परिवार सेक्टर रहा है। वर्ष 2011-12 में पारिवारिक बचत 23.6 प्रतिशत थी जो 2017-18 में गिराकर 17.2 प्रतिशत रह गई। इसमें से लगभग संपूर्ण गिरावट वास्तविक बचतों में हुई, और आंशिक गिरावट 2016-17 तथा 2017-18 में वित्तीय बचतों में हुई (तालिका 1.3)। पारिवारिक वास्तविक बचतों में सोना एवं चांदी तथा निर्माण और मशीनरी और उपकरण सहित भौतिक परिसंपतियां शामिल हैं, जो मिलकर प्रमुख भाग बनाती हैं। वास्तविक बचतों में गिरावट सोने के आयातों में गिरावट अथवा विगत कुछ वर्षों में सोने के आयातों की कम बढ़ोतरी में भी प्रतिबिंबित होती है (चित्र 23)।

1.31 जैसे-जैसे बचत दर गिरी है उसी तरह निवेश दर भी गिरी है। तथापि, निवेश दर में गिरावट बचत दर में गिरावट से अधिक हुई है। जिसके कारण बचत-निवेश अंतर निरंतर कम होता गया है। बचत-निवेश अंतर 2012-13 में जीडीपी के (-) 4.8 प्रतिशत से गिरकर 2017-18 में (-)1.8 प्रतिशत हो गया है। यह जीडीपी के अनुपात में चालू खाता घाटे में हुई गिरावट में भी प्रतिबिंबित होता है।

1.32 मांग का चौथा घटक निर्यात है। निर्यात घरेलू माल की मांग का विदेशी घटक है और आयात अन्य देशों से उत्पादों की मांग के लिए देश की आय का रिसाव होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निर्यातों और आयातों के योगदान के मायने राष्ट्रीय लेखांकन प्रयोजनों के लिए अमरीकी डॉलर की बजाय रुपये के संदर्भों में हैं, इसलिए इस भाग में चर्चा रुपये के संदर्भ में वृद्धि पर आधारित है। दिलचस्प बात है कि निर्यातों और आयातों की बढ़ोतरी की प्रवृत्ति 2018-19 में अलग थी (चित्र 24 व 25)। यद्यपि, निर्यात और आयात, दोनों की वृद्धि अमरीकी डॉलर के संदर्भ में गिरी थी, 2018-19 में यह रूप के संदर्भ में (वर्तमान कीमतों पर) बढ़ी थी। ऐसा 2018-19 में अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन के कारण हुआ था (चित्र 25)।

1.33 वर्ष 2015-16 में निर्यातों में गिरावट आने के पश्चात् 2016-17 में निर्यात वृद्धि का प्रदर्शन बेहतर होना आरंभ हुआ। सेवा तथा वाणिज्य वस्तु, दोनों का निर्यात

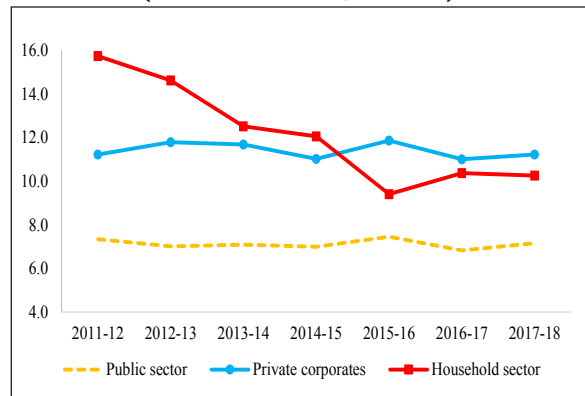
चित्र 19: निवेश दर
(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापित)



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

टिप्पणी: निवेश के आंकड़े और अचल निवेश का क्षेत्रीय विभाजन केवल 2017-18 तक उपलब्ध है।

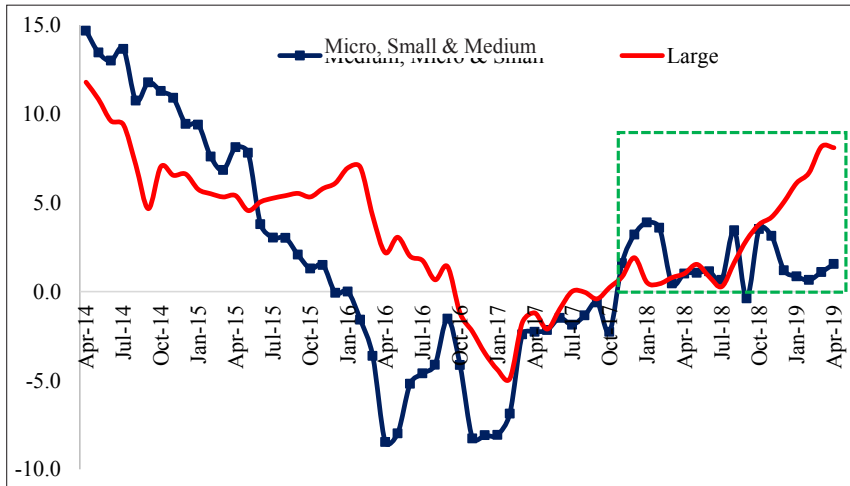
चित्र 20: सेक्टर-वार अचल निवेश दर
(जीडीपी के प्रतिशत भाग)



(रुपये के संदर्भ में) नामिक रूप में 2018-19 में बढ़ा। आयातों की भी नामिक वृद्धि में 2018-19 में तेजी आई परंतु निर्यातों की नामिक वृद्धि बहुत अधिक थी। इसलिए डालर के संदर्भ में यद्यपि निर्यात वृद्धि, गिरी रुपये के संदर्भ में इसमें धनात्मक वृद्धि हुई क्योंकि अवमूल्यन से निर्यात अर्जन में लगातार वृद्धि सुनिश्चित हुई है।

पर निर्यातों की उच्चतर वृद्धि तथा आयातों की कमतर वृद्धि की वजह से जीडीपी की वृद्धि में निवल निर्यातों के योगदान में सुधार आया था। आगे, निर्यात वृद्धि की संभावनाएं वैश्विक व्यापार और वैश्विक संवृद्धि पर बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद और सरकार के निर्यात संवर्द्धन उपायों पर निर्भर है।

चित्र 21: उद्योग सेक्टर में बैंक ऋण का परिनियोजन: माह-वार वृद्धि (प्रतिशत)



आंकड़ा स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

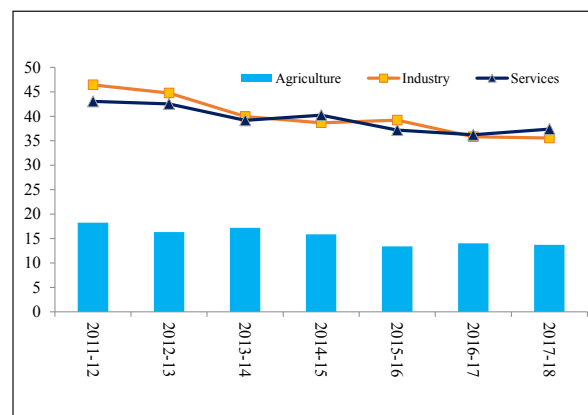
1.34 निर्यात कीमतों की तुलना में आयात कीमतों में विनिमय दर अवमूल्यन तथा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण 2017-18 की तुलना में 2018-19 में रुपये के संदर्भ में तीव्र बढ़ोतरी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में, 2018-19 में वाणिज्य वस्तु के निर्यातों और आयातों के इकाई मूल्य सूचकांक (यूवीआई) में आए परिवर्तन से स्पष्ट होता है। वाणिज्य वस्तु निर्यातों और आयातों के यूवीआई में वृद्धि 2017-18 में क्रमशः 1.1 प्रतिशत और (-) 1.9 प्रतिशत थी परन्तु अप्रैल-दिसंबर 2018-19 में इनमें क्रमशः 6.9 प्रतिशत और 17 प्रतिशत वृद्धि हुई। आयातों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण, 2018-19 में रुपये के संदर्भों में आयातों की वास्तविक वृद्धि की गति धीमी पड़ गई जो संभवतः वर्ष में जीडीपी की वृद्धि में कमी दर्शाती है। दूसरी तरफ, 2018-19 में निर्यातों की वास्तविक वृद्धि तेज हो गई।

1.35 चूंकि भारत निवल रूप से एक आयातक देश है इसलिए निवल निर्यात सदैव ऋणात्मक होते हैं। तथापि, कई वर्षों में निवल निर्यातों की वृद्धि धनात्मक रही है। 2018-19 में, पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर कीमतों

अर्थव्यवस्था का आपूर्ति पक्ष

1.36 सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए), अर्थव्यवस्था के आपूर्ति अथवा उत्पादन पक्ष को प्रतिबिंबित करता है जिसमें बाजार कीमतों पर जीडीपी प्राप्त करने के लिए उत्पादों पर निवल अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है।

चित्र 22: सभी सेक्टरों में जीवीए की तुलना में जीसीएफ का अनुपात



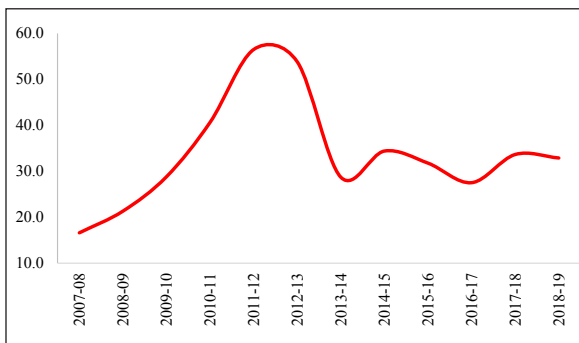
आंकड़ा स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

तालिका 3: जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सकल बचतें

	2011-12	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल बचते	34.6	32.2	31.1	30.3	30.5
सार्वजनिक	1.5	1.0	1.2	1.7	1.7
निजी कॉर्पोरेट	9.5	11.7	11.9	11.5	11.6
परिवार सेक्टर	23.6	19.6	18.0	17.1	17.2
निवल वित्तीय बचत	7.4	7.1	8.1	6.3	6.6
वास्तविक बचत	16.3	12.5	9.9	10.8	10.6

आंकड़ा स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

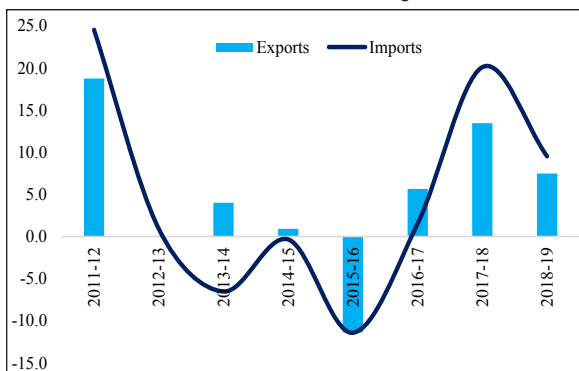
चित्र 23: स्वर्ण आयात
(बिलियन अमरीकी डॉलर में)



आंकड़ा स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता।

जीवीए की वृद्धि आर्थिक गतिविधि में गिरावट को प्रतिबिंबित करती है, जिसने 2017-18 में 6.9 प्रतिशत की अपेक्षा 2018-19 में 6.6 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की (सारणी 1.4)। देश में आर्थिक गतिविधि मंद पड़ने की वजह से 2018-19 में निवल अप्रत्यक्ष करों में 2017-18 की तुलना में 8.8 प्रतिशत की कमतर

चित्र 24: अमरीकी डॉलर के संदर्भ में निर्यातों तथा आयातों में नामिक वृद्धि %

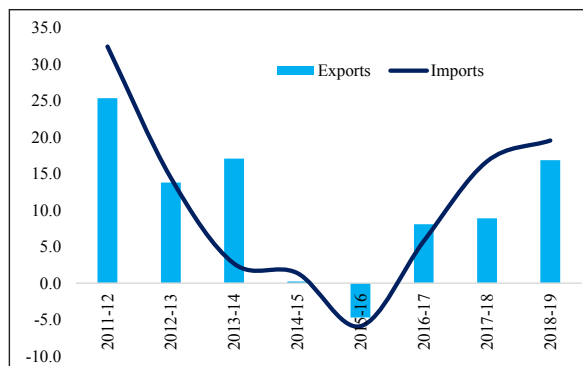


आंकड़ा स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

वृद्धि दर्ज की गई थी।

1.37 दो वर्ष तक अच्छी कृषि वृद्धि के पश्चात् कृषि सेक्टर में वास्तविक वृद्धि 2018-19 में अपेक्षाकृत कम 2.9 प्रतिशत रही (तालिका 1.4)। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2017-18 में खाद्यान्नों के 285 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 2018-19 के दौरान 283.4 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है (अंतिम अनुमान)। वर्ष 2018-19 में खाद्य कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट हुई जैसा कि 2018-19 में लगभग शून्य प्रतिशत उपभोक्ता खाद्य कीमत मुद्रास्फीति से संकेत मिले हैं कि वर्ष में लगातार पांच माह तक कीमतें संकुचित हुई (चित्र 26)। यह कृषि में जीवीए की नामिक मूल्य वृद्धि दर की गिरावट में इस प्रकार प्रतिबिंबित होता है कि जो वृद्धि 2017-18 में 7.0 थी वह वृद्धि दर 2018-19 में कम होकर 4.0 प्रतिशत रह गई। कुल जीवीए में कृषि सेक्टर का भाग निरंतर कम होता जा रहा है और अब 2018-19 में यह 16.1 प्रतिशत पर है।

चित्र 25: रुपये के संदर्भ में –निर्यात–आयात



Data source: Central Statistics Office

तालिका 4: आर्थिक गतिविधि के अनुसार मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि

	वास्तविक वृद्धि (प्रतिशत)			वर्तमान कीमतों पर हिस्सा		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
कृषि, वानिकी एवं मात्स्यकी उद्योग	6.3	5.0	2.9	17.9	17.2	16.1
इंडस्ट्री	7.7	5.9	6.9	29.4	29.3	29.6
खनन और उत्खनन	9.5	5.1	1.3	2.3	2.3	2.4
विनिर्माण	7.9	5.9	6.9	16.8	16.4	16.4
विद्युत, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं सेवाएं	10.0	8.6	7.0	2.5	2.7	2.8
निर्माण	6.1	5.6	8.7	7.8	7.8	8.0
सर्विस	8.4	8.1	7.5	52.7	53.5	54.3
व्यापार, होटल, परिवहन, भण्डारण, प्रसारण सं संबंधित संचार एवं सेवाएं	7.7	7.8	6.9	18.2	18.2	18.3
वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं	8.7	6.2	7.4	20.9	21.0	21.3
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	9.2	11.9	8.6	13.6	14.3	14.7
मूलभूत कीमतों पर जीवीए	7.9	6.9	6.6	100.0	100.0	100.0

आंकड़ा स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

टिप्पण: 2018-19 के लिए आंकड़े अनंतिम अनुमानों के अनुसार हैं।

1.38 भारत में कृषि सेक्टर वृद्धि तथा उत्पादन की दृष्टि से चक्रीय चाल से गुजरता है। नवीतम आंकड़ा श्रृंखला के अनुसार फसल सेक्टर की वृद्धि दर मुख्य रूप से प्रकृति की अनिश्चितताओं के कारण अस्थिर बनी रहती है यद्यपि पिछले चार वर्षों के दौरान पशुधन और मत्स्यकी स्थिर बने रहे। 'कृषि और संबद्ध' सेक्टरों अर्थात् फसल से पशुधन सेक्टर तक तथा फसल सेक्टर के भीतर ही खाद्यान से बागवानी उत्पाद तक में भी मामूली संघटनात्मक बदलाव हुआ है। जीवीए में फसलों का भाग 2013-14 में 12.1 प्रतिशत से कम होकर 2017-18 में 10.0 प्रतिशत रह गया और पशुधन के मामले में इसी अवधि के दौरान (स्थिर कीमतों पर) 4.9 प्रतिशत से कम होकर 4.1 प्रतिशत रह गया।

1.39 विनिर्माण और निर्माण कार्यकलापों में सुधारों के बल पर 2018-19 के दौरान उद्योग की वृद्धि में तेजी आई है (तालिका 4), जिसने अन्य दो उप-सेक्टरों, 'खनन एवं उत्खनन' तथा 'विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं' में मंदी को उम्मीद से अधिक प्रतिसंतुलित कर दिया है। 2018-19 में कुल जीवीए में विनिर्माण का भाग लगभग 16.4 प्रतिशत है, जो 'कृषि

और संबद्ध' सेक्टर के भाग से आंशिक रूप से अधिक है।

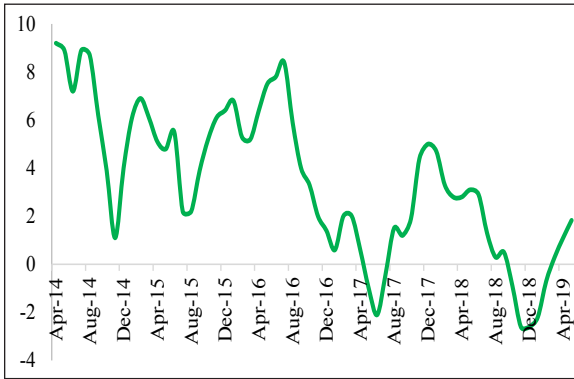
1.40 निजी कॉर्पोरेट सेक्टर का जीवीए जिसका विनिर्माण सेक्टर में लगभग 70 प्रतिशत भाग है (बीएसई और एनसीई के पास सूचीबद्ध कंपनियों के उपलब्ध आंकड़ों से अनुमानित) 2018-19 में स्थिर कीमतों पर 8.4 प्रतिशत बढ़ा। दूसरी तरफ, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईपीपी) द्वारा मापित विनिर्माण सेक्टर में उत्पादन वृद्धि 2017-18 में 4.6 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.5 प्रतिशत हो गई (चित्र 27)। आईपीपी में वृद्धि का उपयोग विनिर्माण सेक्टर के 'अर्ध कॉर्पोरेट' तथा 'असंगठित' खण्ड में जीवीए की वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, अतः 2018-19 में विनिर्माण सेक्टर की वृद्धि में असंगठित क्षेत्र का योगदान गिरकर कम हो गया। विनिर्माण सेक्टर में एक अन्य सकारात्मक गतिविधि हुई है कि वर्ष 2018 के जून माह से बड़े उद्योगों को बैंक ऋण में बढ़ोतरी के साथ-साथ 2016-17 की चौथी तिमाही से विनिर्माण सेक्टर में क्षमता उपयोग में क्रमिक सुधार हुआ है।

1.41 विनिर्माण सेक्टर ने 2018-19 में गति पकड़ी, यद्यपि पहली, दूसरी व तीसरी तिमाही में क्रमशः 12.1

प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष की चौथी तिमाही में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष समाप्त होते-होते यह गति मंद पड़ गई। 2018-19 की अंतिम तिमाही में एनबीएफसी द्वारा उधार कम देने की वजह से वृद्धि दर काफी हद तक मंद हो गई, जिसके फलस्वरूप आंशिक रूप से ऑटो सेक्टर में कम बिक्री हुई। यह मंदी आईआईपी विनिर्माण वृद्धि में भी ज़ाहिर होती है जो 2018-19 की अंतिम तिमाही में काफी हद तक कम हुई जिसके तहत ऑटोमोबाइल (मोटर वाहन और अन्य परिवहन संबंधी उपकरणों का विनिर्माण) सेक्टर में अत्यधिक संकुचन हुआ तथा मूलभूत धातु सेक्टर में बेहद कम वृद्धि हुई। 2018-19 की चौथी तिमाही में वृद्धि की गति मंद पड़ने के बावजूद पीएमआई विनिर्माण 50 से ऊपर रहा, जो विनिर्माण में गतिशील चरण की अबाध गति को प्रतिबिंबित करता है, हालांकि वृद्धि की दर धीमी रही (चित्र 27)।

1.42 निर्माण सेक्टर की वृद्धि का अनुमान सीमेंट के उत्पादन और विनिर्मित इस्पात की खपत की वृद्धि का

चित्र 26: खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट (प्रतिशत)



आंकड़ा स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

उपयोग करके लगाया जाता है। 2018-19 में सीमेंट का उत्पादन तथा विनिर्मित इस्पात की खपत क्रमशः 13.3 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत बढ़ी, 2017-18 में इनकी वृद्धि दरों से अधिक और यह 2018-19 में निर्माण सेक्टर में उच्चतर वृद्धि में प्रतिबिंबित होता है।

1.43 सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक गतिमान सेक्टर है और आर्थिक वृद्धि का प्रमुख चालक रहा है तथा जीवीए का प्रमुख योगदानकर्ता और भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा निर्यातकर्ता है। सेवा निर्यात भारत

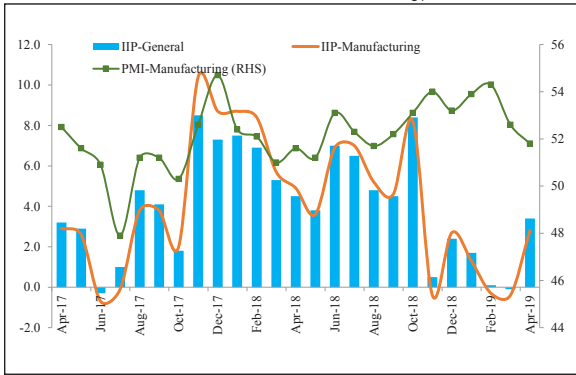
के कुल निर्यातों के मुख्य स्तंभों में से एक बन गया है जो कई गुणा तेजी से बढ़ रहा है। सेवा निर्यात जो 2000-01 में 746 बिलियन रुपये के थे 2018-19 में 14,389 बिलियन रुपये के हो गए हैं, जिससे कुल निर्यातों में इसका भाग 26.8 प्रतिशत से बढ़कर 38.4 प्रतिशत हो गया है। विश्व सेवा निर्यातों में भी भारत की हिस्सेदारी 2005 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 3.5 प्रतिशत हो गई है। यह हिस्सेदारी विनिर्माण निर्यातों की तुलना में कहीं अधिक है, जो 2017 में 1.8 प्रतिशत थी।

1.44 सेवा क्षेत्र वृद्धि 'लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं और 'व्यापार, होटल एवं यातायात' क्षेत्र में वृद्धि में गिरावट के कारण, 2017-18 में 8.1 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 7.5 प्रतिशत हो गई है फिर भी यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मुख्य योगदानकर्ता बना हुआ है। समग्र अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ गई है और अब 54 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर है। सेवा क्षेत्र के भीतर, 'वित्तीय, रीयल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं', 'व्यापार, होटल और यातायात क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा घटक है। पीएमआई सेवाएं अपने विस्तावादी चरण के गैर-समाप्ति को दर्शाते हुए, 2018-19 में 50 अंक से ऊपर बनी रहेंगी।

1.45 'व्यापार, होटल, यातायात, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण' से संबंधित सेवा क्षेत्र की वृद्धि, 2018-19 में 0.9 प्रतिशतांक घट कर 6.9 प्रतिशत रह गई है। यातायात क्षेत्र में वृद्धि का एक प्रतिनिधि, वायु, रेल और जलमार्ग द्वारा परिवहन किए जाने वाले कार्गो की मात्रा है जिसकी वृद्धि 2018-19 (आंकड़ा 29) के दूसरी छमाही में घट गई है। इसके अलावा, वायु, तथा रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, जो कि इस क्षेत्र की वृद्धि का एक सूचक भी है, पिछले वर्ष की तुलना में, 2018-19 में भी घट गया है।

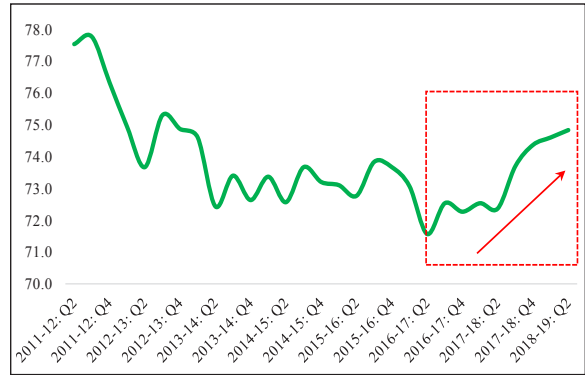
1.46 'वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवा' क्षेत्र ने 2017-18 में 6.2 प्रतिशत की तुलना में, उच्चतर रहते हुए, 2018-19 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के समग्र जीवीए में 20 प्रतिशत से अधिक योगदान करता है। इस क्षेत्र का प्रमुख घटक 'रीयल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं' हैं जिसकी 70% से अधिक की हिस्सेदारी है (संलग्नक में जीडीपी संकलन

चित्र 27: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (प्रतिशत) और पीएमआई सूचकांक



आंकड़ा स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

चित्र 28: चुनिंदा विनिर्माण कंपनियों का क्षमता उपयोग (प्रतिशत) (3 तिमाहियों का गतिशील औसत)



आंकड़ा स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

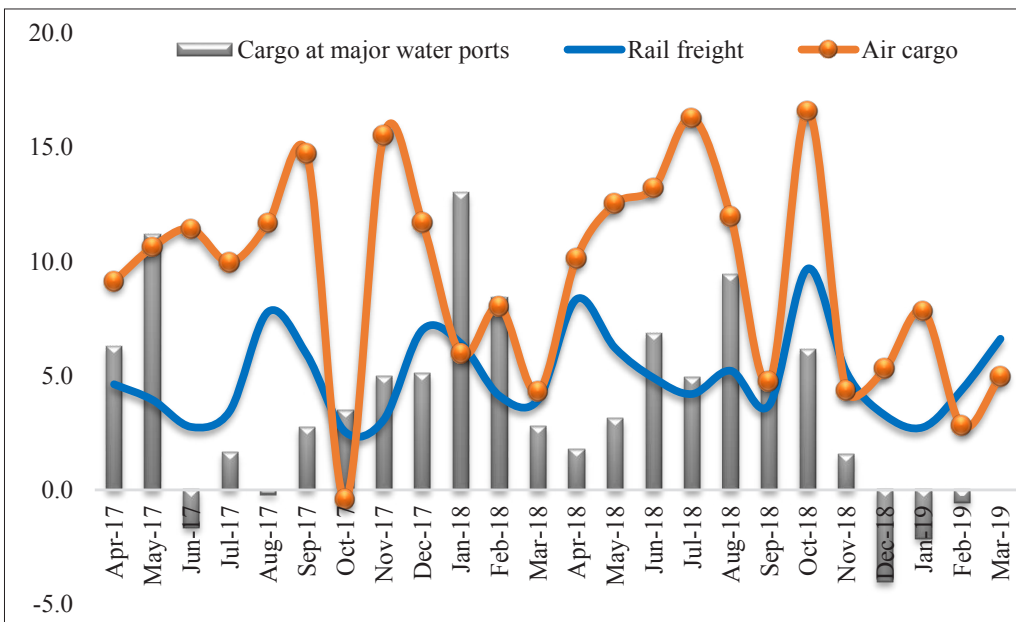
प्रणाली का संदर्भ लें)। इस क्षेत्र का वित्तीय सेवाएं घटक बैंक ऋण तथा बैंकों में जमा की वृद्धि दर का उपयोग करते हुए, अनुमानित है, जो वित्तीय सेवाओं में जीवीए में वृद्धि दर्शाते हुए, पिछले वर्ष में क्रमशः 10.0 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत की तुलना में, 2018-19 में क्रमशः 14.5 प्रतिशत तथा 10.0 प्रतिशत पर बढ़ा है।

1.47 संघ सरकार का ब्याज भुगतान से निवल राजस्व व्यय पिछले वर्ष में 11.3 प्रतिशत की तुलना में , 2018-19 में 5.6 प्रतिशत तक बढ़ा है। यह 'लोक प्रशासन रक्षा, तथा अन्य सेवाओं की वृद्धि दर' में प्रदर्शित

होता है, (जो ब्याज भुगतान को घटाकर राजस्व व्यय की वृद्धि दर का उपयोग कर के परिकल्पित होता है), वह 2017-18 में 11.9 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 8.6 प्रतिशत रह गया है।

1.48 सभी क्षेत्रों, श्रम, पूंजीगत और उद्यमिता से आय में हिस्सेदारी की रचना पृथक् होती है। कृषि में श्रम को होने वाली आय की हिस्सेदारी बहुत कम है। क्योंकि इस क्षेत्र में भुगतान आधारित श्रम की केवल मामूली सी उपस्थिति है जो कर्मचारियों के मुआवजे (सीई) की बहुत कम हिस्सेदारी में प्रदर्शित होती है। चूंकि अधिकतर

आंकड़ा 29: यातायात के विभिन्न साधनों द्वारा कार्गो के परिवहन में वृद्धि



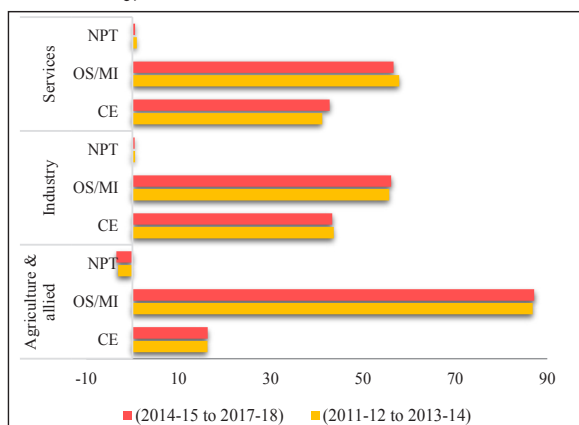
आंकड़ों का स्रोत: नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय।

व्यक्ति अपने स्वयं के खेतों में कार्य करते हैं, अतः प्रचालनात्मक अधिशेष (ओएस)/मिश्रित आय (एमआई) की कृषि के जीवीए में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। दूसरी ओर, उद्योग और सेवाएं क्षेत्र अपने जीवीए में कर्मचारियों के मुआवजे की उच्च हिस्सेदारी दर्शाता आ रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती ही रही है (चित्र 30)।

अर्थव्यवस्था की संभावनाएं

1.49 वर्ष, 2019-20 ने सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक जनादेश प्रदान किया है, जो उच्च आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं की शुभ सूचना देता है। पूरे

चित्र 30: विभिन्न आय श्रेणियों में निवल मूल्यवर्धित हिस्सेदारी (प्रतिशत)



आंकड़े का स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

टिप्पणी: सीई-कर्मचारियों का मुआवजा, सीएफसी: अचल पूंजी का उपभोग, ओएस: प्रचालनात्मक अधिशेष।

एमआई: स्व रोजगार की मिश्रित आय, एनपीटी:

निवल उत्पादन कर

2018-19 में संवृद्धि की गति में कुछ धीमेपन के बाद अर्थव्यवस्था में बहाली दर्शाते हुए वर्ष, 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहनी अनुमानित है। वर्ष, 2019-20 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि होनी संभावित है क्योंकि वृहत अर्थव्यवस्था की स्थितियों के स्थिर बने रहने की संभावना है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए संरचनात्मक सुधार उपाय आगे भी जारी रहेंगे, फिर भी, 2019-2020 में नकारात्मक जोखिम और विपरीत संभावनाएं दोनों जारी हैं।

1.50 निवेश दर जो 2011-12 से गिर रही थी, निम्नतम

स्तर पर पहुंच गई प्रतीत होती है। उच्च ऋण वृद्धि तथा मांग में सुधार होने के बल पर वर्ष, 2019-20 में इस निवेश दर के बढ़ने की संभावना है। देश में राजनीतिक स्थिरता आर्थिक संभावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ा सकती है, जबकि कारोबार संभावनाओं में उच्च क्षमता का उपयोग और इजाफा 2019-20 में निवेश गतिविधियों को बढ़ा सकता है। वर्ष के आरंभ में, ऋण व्यवस्थापरक आर्थिक नीति, यदि जल्दी से संप्रेषित हो जाती है तो वास्तविक ऋण दरों को घटाने में मदद मिल सकती है। बैंकिंग क्षेत्र में दबावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के संकेत है जैसा कि दिसम्बर, 2018 को रही स्थिति के अनुसार सकल अग्रिम अनुपात के लिए अनर्जक परिसंपदाओं में कमी दिखाई दी है, जो पूंजीगत खर्च चक्र को बल दे सकती है।

1.51 अर्थव्यवस्था के विकास मार्ग का निर्धारण करने के लिए उपभोग का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। ग्रामीण मजदूरी वृद्धि जो कम हो रही थी, ऐसा लगता है कि निम्नतम स्तर पर आ गई है और 2018 के मध्य से इसमें वृद्धि शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि से ग्रामीण मांग बढ़ने में मदद मिलनी चाहिए। खाद्य कीमतें बढ़ने से ग्रामीण आय और खर्च की क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए और इसलिए ग्रामीण उपभोग की मांग बढ़ सकती है। प्रधान मंत्री किसान योजना की घोषणा सरकार द्वारा 2 हेक्टेयर तक संयुक्त रूप से भूमि धारित/स्वामी छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता देने हेतु की गई थी। सभी किसानों को लाभ देने के लिए न्यूनतम भूमि धारिता की शर्त को बाद में हटा दिया गया है।

1.52 2018-19 में तेल के दाम 14 अमेरिकी डॉलर/प्रति बैरल तक बढ़ गए हैं, फिर भी, वर्तमान स्तर (2019-20 के लिए तेल की भावी कीमत के आधार पर) से इनके 2019-20 में घटने की संभावना है। यह उपभोग में एक सकारात्मक बल प्रदान कर सकता है।

1.53 तथापि, उपभोग में नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं। कृषि क्षेत्र में पुनः लाभ की सीमा और कृषि की कीमतें ग्रामीण खपत को बल देने का निर्णय लेगी, जो मानसून की स्थिति पर भी निर्भर करता है। मौसम सूचना विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष देश में पूर्ण रूप से

सामान्य वर्षा होने की संभावना है। इससे कृषि क्षेत्र की वृद्धि में बेहतरी आ सकती है। फिर भी, आईएमडी के अनुसार कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई है। यह कुछ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यदि एनबीएफसी क्षेत्र का प्रभाव इस वर्ष से और आगे पड़ता है तो इससे एनबीएफसी से ऋण कम लिया जा सकता है और खर्च में उच्च वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

1.54 यदि यथास्थिति बनाई रखी जाए तो 2019-2020 के लिए निर्यात वृद्धि के कमजोर रहने की संभावना है। तथापि, हमारी अपनी सापेक्ष प्रतिस्पर्धी लाभ के आधार देशों/बाजारों को लक्ष्य बनाने के लिए निर्यात नीतियों का पुनर्अभिमुखीकरण और भारतीय माल के सम्पर्क में आयातक देशों के आने से निर्यात के प्रदर्शन

में मदद मिलेगी। यथास्थिति बनी रही तो 2019 में विश्व अर्थव्यवस्था की संभावना अंधकारमय है। विश्व अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बीच व्यापार में तनाव बढ़ने से उत्पन्न खतरे का सामना कर रही है, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला, ब्रेकिजट के परिणाम और चीन की वृद्धि में कमी के जोखिम से बड़े पैमाने पर उथल-पुथल हो सकती है। विश्व में संवृद्धि में कमी और व्यापार में तनाव से बढ़ती अनिश्चितता निर्यात की मांग पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकती है, जिससे भारत सहित कई देशों, की जीडीपी की वृद्धि दर और कम होगी।

1.55 कुल मिलाकर, 2019-20 में 7 प्रतिशत की संभावित संवृद्धि अर्थव्यवस्था की दशाओं के बेहतर होने का संकेत कर रही है।

अध्याय एक नजर में

जीडीपी की वृद्धि दर 2017-18 में 7.2 प्रतिशत से कम होकर 2018-19 में 6.8 प्रतिशत रह गई तथापि, अभी भी भारत सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बना हुआ है।

वृद्धि की गति में यह नरमी मुख्य रूप से कृषि एवं संबद्ध व्यापार, होटल, परिवहन, भण्डारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं तथा लोक प्रशासन एवं रक्षा क्षेत्र में कम वृद्धि के कारण आई है।

निवेश में वृद्धि, जो अनेक वर्षों में कम थी, सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है और 2017-18 से इसमें सुधार आना शुरू हुआ है। अचल निवेश में वृद्धि 2016-17 में 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 9.3 प्रतिशत तथा 2018-19 में और अधिक 10.0 प्रतिशत हो गई।

मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के भीतर नियंत्रित करके और चालू खाता घाटा जीडीपी के अनुपात में बनाए रखकर भारत अपनी समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए हुए हैं।

केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा 2018-19 में जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। अप्रैल-दिसंबर 2018 में चालू खाता घाटा 2.6 प्रतिशत था।

सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक परिसंपदाएं मार्च अंत 2018 में 11.5 प्रतिशत से घटकर दिसंबर अंत 2018 में 10.1 प्रतिशत रह गईं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना निजी निवेश में तेजी और मजबूत उपभोग वृद्धि की पृष्ठ भूमि पर 2019-20 में वृद्धि में तेजी आने की संभावना के चलते उज्ज्वल प्रतीत होती है।

अनुलग्नक

तालिका: जीडीपी अनुमान की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयोग किए गए प्रमुख आंकड़ा स्रोत तथा सूचक

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
कृषि	<p>वर्तमान कीमतें:</p> <p>फसलें:</p> <p>उत्पादन: खाद्यान्न उत्पादन के लिए चौथा अग्रिम और बागवानी कृषि फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन दोनों के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान/अंतिम अनुमान जनवरी तक यथा उपलब्ध, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएजीएफडब्ल्यू) द्वारा प्रकाशित।</p> <p>कीमतें: फसलों (श्रेणी विशेष) के थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) उसी राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय (राज्य डीईएस) द्वारा की गई पिछले वर्ष की कीमतों जानकारी का प्रयोग किया जाता है।</p> <p>पशुधन:</p> <p>उत्पादन: एमओएजीएफडब्ल्यू द्वारा प्रमुख पशुधन उत्पादन के संबंध में नवीनतम आंकड़े।</p> <p>कीमतें: कीमतों की जानकारी तदनुसारी राज्य डीईएस द्वारा प्रदान की जाती है। यदि कुछ राज्य डीईएस कीमतों को अंतिम रूप नहीं देते हैं तो वस्तु-वार, डब्ल्यूपीआई, उसी राज्य डीईएस द्वारा आपूर्ति किए गए पिछले वर्ष की कीमतों का प्रयोग किया जाता है।</p>	<p>फसलों और बागवानी फसलों का अनुमान, एमओएजीएफडब्ल्यू द्वारा लगाया जाता है। कुछ राज्य विशेष की फसलों का अद्यतन उत्पादन आंकड़ा उसी राज्य डीईएस द्वारा दिया जाता है। राज्यों से तुलनीय विचार-विमर्श के बाद मूल्य संबंधी आंकड़ा अद्यतन किया जाता है।</p>	<p>कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तुलनीय विचार-विमर्श के दौरान विशिष्ट फसल तथा संशोधित मूल्य उपलब्ध कराए जाते हैं। उत्पाद द्वारा खेती दरों की वर्तमान लागत संकलन के लिए प्रयोग की गई।</p>

¹ अग्रिम और अंतिम अनुमानों के लिए कृपया आर्थिक समीक्षा खण्ड - 2, 2017-18 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रथम अग्रिम अनुमान, द्वितीय अग्रिम अनुमान और अंतिम अनुमान में संकेत आधारित पद्यति अपनाई गई है। ये सभी अनुमान 7 से 9 महीने तक के आंकड़ों पर आधारित हैं। पहला संशोधित अनुमान जनवरी में जारी किया गया था और उसके बाद के वर्षों में द्वितीय और तृतीय संशोधित अनुमान जारी किये गये थे। जैसे वर्ष 2015-16 के लिए प्रथम संशोधित अनुमान जनवरी 2017 में जारी किया गया था। द्वितीय संशोधित अनुमान जनवरी 2018 और तृतीय संशोधित अनुमान जनवरी 2019 में जारी किया गया था।

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
	<p>सिंचाई प्रणाली:</p> <p>केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बजट कागजातों और सार्वजनिक क्षेत्र की सिंचाई कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों का विश्लेषण करके मौजूदा कीमतों पर जीवीए का अनुमान लगाया जाता है।</p> <p>फसलें और पशुधन</p> <p>वर्तमान वर्ष के उत्पादन को आधार वर्ष की कीमतों द्वारा गुना किया जाता है।</p> <p>सिंचाई तंत्र</p> <p>आधार वर्ष के जीवीए अनुमानों को सरकारी नहरों द्वारा सिंचाई के सूचक के साथ प्रयोग किया जाता है।</p>		
वानिकी	<p>वर्तमान कीमतों पर: राज्य वन उद्योग विभागों से नवीनतम उत्पादन तथा कीमतों के आकड़े प्राप्त किए जाते हैं और श्रेणी विशिष्ट डब्ल्यूपीआई (इस्तेमाल किया जाता है जब किसी राज्य से कीमतें उपलब्ध नहीं होती हैं)। दर्ज उत्पादन को 1.1 से गुणा कर वास्तविक उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है।</p> <p>स्थिर कीमतों पर: नवीनतम उत्पादन और आधार वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है।</p>		?
मात्स्यिकी	<p>वर्तमान कीमतों पर:</p> <p>उत्पादन: एमओएजीएफडब्ल्यू के मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन सांख्यिकीय (एएचएस) प्रभाग एवं राज्य मत्स्य पालन विभागों से तटीय मछलियों, समुद्रीय मछलियों और क्यूरिंग गतिविधियों का नवीनतम आंकड़ा</p> <p>कीमतें: कीमतें संबद्ध राज्य डीईएस द्वारा प्रदान की जाती हैं। यदि कुछ राज्य डीईएस कीमतों को अंतिम रूप नहीं देते हैं तो मछली का डब्ल्यूपीआई, उसी राज्य डीईएस द्वारा निर्धारित किए गए पिछले वर्ष की कीमत पर प्रयोग किया जाता है।</p> <p>स्थिर कीमतों पर: नवीनतम उत्पादन और आधार वर्ष कीमतों का उपयोग किया जाता है।</p>	क्यूरिंग गतिविधियों पर अद्यतन उत्पादन एवं मूल्य अनुमान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नवीनतम आंकड़े प्रदान किए जाते हैं।	तुलनीय विचार-विमर्श के बाद उत्पादन का संशोधन, क्यूरिंग गतिविधियों पर सूचना और कीमत में संशोधन किए जाते हैं।
खनन और खदान	<p>वर्तमान कीमतों पर:</p> <p>सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें; गैर-सरकारी कार्पोरेट क्षेत्र के लिए एमसीए-21, नमक के उत्पादन के लिए नमक आयुक्त, लघु खनिज पदार्थ के लिए राज्य भूगर्भ विभाग।</p>		

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
	<p>स्थिर कीमतों पर:</p> <p>भारतीय खान ब्यूरो से मुख्य खनिजों के लिए निर्विवाद कीमत अपस्थापक (आईपीडी) और कोयले तथा पेट्रोलियम के स्थिर कीमतों के अनुमान के लिए विशिष्ट श्रेणी डब्ल्यूपीआई उपयोग किया गया है।</p>		
विनिर्माण-क्षेत्र	<p>वर्तमान कीमतों पर:</p> <p>सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण-क्षेत्र की कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें, उद्यम विभाग (डीई) के बजट कागजात, गैर सरकारी कार्पोरेट क्षेत्र के लिए एमसीए-21*, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण तथा एनएसएस रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण तथा आधार वर्ष के लिए अनिगमित सर्वेक्षण आंकड़ा इस्तेमाल किया गया और उसके आईआईपी द्वारा आगे बढ़ाया गया तथा डब्ल्यूपीआई (एसआई के आंकड़े की अनुपस्थिति में)</p> <p>स्थिर कीमतों पर: स्थिर कीमतों पर अनुमान के लिए अपस्थापक रूप में थोक कीमत सूचकांक, विनिर्माण क्षेत्र (क्षेत्र-विशेष) उपयोग किया जाता है।</p>		
बिजली	<p>वर्तमान कीमतों पर: विभागीय उद्यमों के बजट दस्तावेज, इलैक्ट्रिसिटी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें, गैर सरकारी क्षेत्र के लिए एमसीए-21</p> <p>स्थिर कीमतों पर: आधार कीमत अनुमान, गैस की मात्रा सूचकांक (उत्पादन का मात्रा का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया) और जल आपूर्ति के लिए सीपीआई का प्रयोग किया जाता है।</p>		
गैस एवं जल आपूर्ति	<p>वर्तमान कीमतें:</p> <p>एमसीए-21 एवं वार्षिक रिपोर्टें, एनएसएस परिणाम कारपोरेट ग्रोथ व केवीआईसी द्वारा आगे ले जाये गये।</p> <p>स्थिर कीमतें: आधार वर्ष के अनुमान जलापूर्ति के लिए गैस एवं सीपीआई के मात्रात्मक सूचकांक (उत्पादन परिमाण के प्रयोग से सृजित) के साथ परिचालित है।</p>		
निर्माण	<p>वर्तमान कीमतों पर:</p> <p>पक्का निर्माण: आवास में पक्का निर्माण, अन्य भवन तथा संरचना (डीओबीएस) के अनुमान के संकलन के लिए उत्पाद प्रवाह विधि का उपयोग किया जाता है। निर्माण सामग्री अर्थात् सीमेंट, लोहा और स्टील, इंटे, टाइलें, लकड़ी, गोल लकड़ी, कोलतार और कोलतार मिश्रण तथा शीशा और शीशे के उत्पाद, फिक्सचर तथा फिटिंग्स आदि का ऑनसाइट मूल्य, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एसआई) के परिणामों का इस्तेमाल करते हुए, आधार वर्ष, 2011-12 के लिए संकलित किया गया था। इसके अलावा, व्यापार और परिवहन लाभ भी जोड़ दिए गए थे। आधार वर्ष अनुमान, भावी वर्षों के लिए विशेष संकलन श्रेणियों को विनिर्माण जीवीओ की वृद्धि द्वारा और आगे ले जाते हैं। पक्का निर्माण के जीवीए पर पहुंचने के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किए गए निर्माण के संबंध में अध्ययन पर आधारित दरों और अनुपातों का इस्तेमाल किया जाता है।</p>		

² संशोधित अनुमान में केवल सामान्य कंपनियों की वृद्धि में एमसीए 21 डाटा का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरी आईआईपी कंपनियों के फील्ड रिटर्न होते हैं।

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
	<p>कच्चा निर्माण: कच्चा निर्माण के अनुमान में व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। कच्चा डीओबीएस भूमि सुधार, सिंचाई, खनिज खोडा, पौधारोपण आदि पर निर्माण गतिविधियों को कच्चा निर्माण के रूप में माना जाता है। उक्त गतिविधियों पर विभिन्न संस्थानागत क्षेत्रों द्वारा किए गए व्यय का 75 प्रतिशत कच्चा निर्माण के जीविए का गठन करता है।</p> <p>स्थिर कीमतों पर: उपयुक्त डब्ल्यूपीआई तथा सीबीआई आधारित अपस्थायकों का इस्तेमाल करते हुए अनुमान संकलित किए जाते हैं।</p>		
व्यापार और मरम्मत सेवाएं	<p>वर्तमान कीमतों पर: डीई का बजट दस्तावेज, एनडीई की वार्षिक रिपोर्ट, गैर-सरकारी कार्पोरेट क्षेत्र के लिए एमसीए-21 आंकड़ा, अर्द्ध-निगम क्षेत्र के लिए बिक्री कर टर्नओवर (ट्रेड क्षेत्र हेतु) के असंगठित सूचकांक द्वारा आगे भेजे गए एनएसएस परिणाम, सेवा क्षेत्र वृद्धि दर (मरम्मत सेवा हेतु), मोटर वाहनों की बिक्री में वृद्धि (मोटर वाहनों और मोटर साइकलों की रख-रखाव तथा मरम्मत हेतु)।</p> <p>स्थिर कीमतों पर: भारत डब्ल्यूपीआई और वाहनों की बिक्री में वृद्धि।</p>		
होटल तथा रेस्तरां	<p>वर्तमान कीमतों पर: आधार वर्ष में एनडीई की वार्षिक रिपोर्ट, गैर-सरकारी कार्पोरेट क्षेत्र के लिए एमसीए-21 आंकड़ा, असंगठित क्षेत्र हेतु एनएसएस निष्कर्ष तथा बाद में निगमित क्षेत्र की वृद्धि का इस्तेमाल किया जाता है।</p> <p>स्थिर कीमतों पर: भारत डब्ल्यूपीआई को एक अपस्थापक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।</p>		
रेल परिवहन	<p>वर्तमान कीमतों पर: विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लिए केन्द्रीय बजट दस्तावेज, गैर-सरकारी कार्पोरेट क्षेत्र के एमसीए-21 आंकड़ा और गैर-विभागीय वाणिज्य उपक्रमों के लिए वार्षिक रिपोर्ट से नवीनतम उपलब्ध अनुमान।</p> <p>स्थिर कीमतों पर: आधार वर्ष के रूप में भारत में उनकी आय के साथ यात्रियों से आय, सामान से आय आदि के भारत मात्रा सूचकांक का इस्तेमाल करते हुए मात्रा बहिर्वेशन।</p>		
अन्य भूमि, जल, वायु परिवहन	<p>क्षेत्र के लिए एमसीए-21 आंकड़ा, वाहनों की वृद्धि का इस्तेमाल करते हुए, आगे भेजी गई जानकारी परिवहन असंगठित क्षेत्र का एनएसएस निष्कर्ष (सीपीआई-परिवहन तथा संचार का इस्तेमाल करते हुए बढ़े हुए वर्तमान मूल्य हेतु)।</p> <p>स्थिर कीमतों पर: परिवहन (भूमि परिवहन हेतु) का मात्रा सूचकांक, वायु मात्रा सूचकांक (वायु परिवहन हेतु), संभाले गए कार्गो का सूचकांक (जल परिवहन), सड़क जल एवं वायु की संयुक्त वृद्धि (परिवहन की आपात सेवा हेतु)।</p>		
संचार	<p>वर्तमान कीमतों पर: डाक विभाग के बजट दस्तावेज, एनडीई (बीएसएनएल, एमटीएनएल) और की वार्षिक रिपोर्ट, गैर सरकारी कार्पोरेट क्षेत्र हेतु एमसीए-21 आंकड़ा, सेवा कर वृद्धि प्रसारण (कूरियर, केबल तथा दूरसंचार हेतु) और कार्पोरेट वृद्धि (रिकॉर्डिंग, प्रकाशन तथा प्रसारण सेवा हेतु) का इस्तेमाल करते हुए एनएसएस द्वारा असंगठित क्षेत्र द्वारा चलाया जाता है।</p> <p>स्थिर कीमतों पर: वृद्धि तथा सीपीआई-परिवहन तथा संचार के उपयोग का कार्यवृत्त</p>		

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
एनबीफआई एवं वित्तीय सहायिकाओं सहित बैंकिंग	<p>वर्तमान कीमतों पर:</p> <p>राष्ट्रीयकृत बैंकों का वार्षिक लेखा आंकड़ा, गैर-सरकारी बैंकों, विदेशी बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई डाटा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा ग्रामीण सहकारी बैंकों हेतु नाबार्ड आंकड़ा, वित्तीय सहायिकाओं के लिए सेबी आंकड़ा एनबीएफआई और वित्तीय सहायिकाओं हेतु एमसीए आंकड़ा, अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण से सर्वेक्षण आंकड़ा निजी ऋणदाताओं के संबंध में आरबीआई रिपोर्ट तथा उद्यम सर्वेक्षणों का 67 वें राउंड का आंकड़ा एवं असंगठित क्षेत्र के लिए परिवारों हेतु ऋणों तथा अग्रिमों पर आरबीआई आंकड़ा, बजट कागजातों को डाकघर बचत बैंक के जीवीए अनुमान हेतु इस्तेमाल किया जाता है।</p> <p>स्थिर कीमतों पर:</p> <p>स्थिर मूल्य पर जीवीए का अनुमान प्रत्येक उप-क्षेत्रों के लिए अलग से तैयार किया जाता है। सामान्यतः आधार वर्ष के अनुमान को उस उप-क्षेत्र में गतिविधि की मात्रा मापने वाले सूचकांको का इस्तेमाल करते हुए आगे भेजा जाता है (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के भारत में अवस्थित बैंकों से संबंधित वार्षिक सांख्यिकीय तालिकाओं से आंकड़े का इस्तेमाल करते हुए, बैंकों हेतु कुल जमा एवं ऋण वृद्धि उत्पन्न की जाती है)। यदि जहां गतिविधि की मात्रा को मूल्य के संबंध में अर्थात् वर्तमान मूल्य में मापा जाता है तो वही मात्रा सूचकांक प्राप्त करने के लिए गैर वित्तीय क्षेत्रों के निर्विवाद निहित कीमत अपस्थापक द्वारा अपस्थितिकारक होते हैं।</p>	<p>वर्तमान कीमतों पर:</p> <p>आंकड़ा, एमसीए, नाबार्ड, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एनएफएससीओबी) तथा राज्य वित्तीय निगमों, केन्द्रीय तथा राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय कंपनियों एवं निगमों और डाकघर बचत बैंक से बजट कागजातों से नवीनतम आंकड़ों के आधार पर अद्यतन किया जाता है।</p> <p>स्थिर कीमतों पर:</p> <p>निर्विवाद कीमत अपस्थापक भी गैर वित्तीय क्षेत्र के लिए वर्तमान तथा स्थिर मूल्यों में संशोधित अनुमान के आधार पर उद्यतन किया जाता है।</p>	

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
बीमा और पेंशन	<p>वर्तमान कीमतों पर: सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन तथा वर्तमान मूल्य तथा स्थिर कीमत गैर जीवन बीमा कंपनियों के वार्षिक लेखा से दोनों में आईआरडीआई, प्राप्त आंकड़ा, गैर सरकारी बीमा कंपनियों के पीएफआरडीए से प्राप्त नवीनतम लिए आईआरडीआई आंकड़ा, पेंशन निधियों आंकड़ों और बजट दस्तावेजों के कि लिए पीएफआरडीए आंकड़ा तथा डाक विश्लेषण के आधार पर आंकड़ा जीवन बीमा के लिए बजट दस्तावेजों का अद्यतन किया जाता है। स्थिर इस्तेमाल किया जाता है। मूल्य अनुमान में निर्विवाद मूल्य स्थिर कीमतों पर:</p> <p>स्थिर मूल्यों पर जीवीए का डिफ्लेटर को भी गैर वित्तीय क्षेत्र अनुमान प्रत्येक उप-क्षेत्र के लिए अलग से हेतु वर्तमान तथा स्थिर मूल्यों में तैयार किया जाता है। सामान्यतः आधार वर्ष संशोधित अनुमान के आधार पर अनुमान उसी उप-क्षेत्र में गतिविधियों की अद्यतन किया जाता है।</p>	<p>मात्रा (सार्वजनिक गैर जीवन बीमा के लिए प्रीमियम मुक्त पुनः इंश्योरेंस तथा अदा किए गए दावों का इस्तेमाल करते हुए उस अवस्था के लिए) को मापते हुए सूचकांकों का आगे इस्तेमाल किया जाता है। उन मामलों में जहां मूल्य के संबंध में अर्थात् वर्तमान मूल्यों में गतिविधियों की मात्रा मापी जाती है तो इन्हें मात्रा सूचकांक प्राप्त करने के लिए गैर वित्तीय क्षेत्रों के निहित कीमत अपस्थापक द्वारा अपस्थापन होता है।² हैं। डाक जीवन बीमा के लिए वर्तमान मूल्य जीवीए समग्र अखिल भारतीय सीपीआई का उपयोग करते हुए अपस्थापन होता है।</p>	
स्थावर संपदा	<p>वर्तमान कीमतों पर: एनडीई की वार्षिक रिपोर्टें, एमसीए-21 आंकड़ा, कॉरपोरेट क्षेत्र की वृद्धि सहित आगे भेजे गए असंगठित क्षेत्र के लिए एनएसएस परिणाम।</p> <p>स्थिर कीमतों पर: स्थिर कीमतों पर अनुमान के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है।</p>		
आवासों का स्वामित्व:	<p>वर्तमान कीमतों पर:</p> <p>आधार वर्ष के लिए सीईएस से प्राप्त सकल किराया 3 प्रति परिवार मकान (शहरी)* किराया गणना। आधार वर्ष के लिए बाद के वर्षों हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रति परिवार किराया मकान के किराये (शहरी क्षेत्र) के सूचकांक का इस्तेमाल करते हुए बहिर्वेशन किया जाता है। तथा आवासों की संख्या का शहरी मकान की अंतर सेंशल वृद्धि दर का इस्तेमाल करते हुए बहिर्वेशन किया जाता है।</p> <p>ग्रामीण क्षेत्र के आवासों के लिए ग्रामीण आवासीय भवनों के पूंजीगत स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है।</p> <p>स्थिर कीमतों पर: शहरी क्षेत्रों के लिए आवासों की अंतर-सेंशल वृद्धि-दर के साथ आधार वर्ष अनुमान और ग्रामीण आवासों के लिए सीपीआई (ग्रामीण) द्वारा अस्थापित होते हैं।</p>		
व्यावसायिक सेवाएं	<p>वर्तमान कीमतों पर:</p> <p>एनडीई की वार्षिक रिपोर्टें, एमसीए-21 आंकड़ा, कॉरपोरेट क्षेत्र की वृद्धि सहित आगे भेजे गए असंगठित क्षेत्र के लिए एनएसएस परिणाम।</p> <p>स्थिर कीमतों पर:</p> <p>स्थिर कीमतों पर अनुमान के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है।</p>		

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
लोक प्रशासन और रक्षा	वर्तमान कीमतों पर: एलबी और स्वायत्त संस्थान आंकड़े के साथ केन्द्र तथा राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त संशोधित अनुमान।	कीमतों पर: एलबी और स्वायत्त संस्थान आंकड़े के साथ केन्द्र तथा राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त वास्तविक अनुमान।	कीमतों पर: एलबी और स्वायत्त संस्थान आंकड़े के साथ केन्द्र तथा राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त वास्तविक अनुमान (तुलनीय विचार-विमर्श पर आधारित कोई संशोधन)
	स्थिर कीमतों पर: निवल मूल्य संवर्धन के वर्तमान कीमतों पर अनुमान पर सीपीआई का इस्तेमाल करते हुए अस्थापन करते हैं तथा स्थिर कीमतों पर निश्चित पूंजी की खपत जीवीय पर पहुंचने के लिए जोड़ी जाती है।		
उत्पाद कर	वर्तमान कीमतों पर: एलबी और स्वायत्त संस्थान आंकड़े के साथ केन्द्र तथा राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त संशोधित अनुमान।	वर्तमान मूल्य: एलबी और स्वायत्त संस्थान आंकड़े के साथ केन्द्र तथा राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त वास्तविक अनुमान।	वर्तमान मूल्य: एलबी और स्वायत्त संस्थान आंकड़े के साथ केन्द्र तथा राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त वास्तविक अनुमान (तुलनीय विचार-विमर्श पर आधारित कोई संशोधन)
	स्थिर मूल्य: उत्पादों पर करों का स्थिर कीमतों पर अनुमान मात्रा बहिर्वेशन द्वारा संकलित होता है। विभिन्न उत्पाद करों के लिए मात्रा बहिर्वेशन अलग से किया जाता है। बहिर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया गया सूचकांक विनिर्माण, सेवाओं इत्यादि की निपज की मात्रा में वृद्धि होती है।		

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
उत्पाद सब्सिडियां	वर्तमान कीमतों पर: एलबी और स्वायत्त संस्थान आंकड़े के साथ केन्द्र तथा राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त संशोधित अनुमान।	वर्तमान कीमतों पर: एलबी और स्वायत्त संस्थान आंकड़े के साथ केन्द्र तथा राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त वास्तविक अनुमान।	वर्तमान कीमतों पर: एलबी और स्वायत्त संस्थान आंकड़े के साथ केन्द्र तथा राज्यों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त वास्तविक अनुमान। (तुलनीय विचार-विमर्श पर आधारित कोई संशोधन)।
	स्थिर कीमतों पर: व्यक्तिगत घटक सीपीआई तथा डब्ल्यूपीआई सूचकांकों का इस्तेमाल करते हुए अपस्थापन करते हैं और स्थिर कीमतों पर जीएफसीई प्राप्त करने के लिए स्थिर कीमतों पर सीएफसी को जोड़ा जाता है।		

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
गैर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	<p>वर्तमान कीमतों पर अंतिम उपभोग व्यय</p> <p>(क) कृषि: गैर सरकारी अंतिम उपभोग प्राप्त करने के लिए उत्पाद की मात्रा, चारे और बीज के लिए इस्तेमाल की गई राशि, कचरा, लोक वितरण प्रणाली (उपभोक्ता मामले मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ा), अंतर उद्योग खपत, सरकारी उपभोग और स्व-उपभोग के लिए रखे गए उत्पादों को घटाया जाता है।</p> <p>(ख) विनिर्माण:</p> <ul style="list-style-type: none"> गणना के लिए एएसआई आंकड़े तथा संगठित विनिर्माण के लिए उत्पाद द्वारा परिकलित की जाती हैं। उसके बाद इस एएसआई का प्रयोग कर संगठित विनिर्माण उत्पादन में से अन्तिम उपभोग के पदार्थों का तथा उपभोज्य पदार्थों का अंश आंकलित करते हैं। इनके अनुपात का उपयोग सार्वजनिक, निजी निगम क्षेत्र तथा निजी गैर निगम क्षेत्रों के उत्पादनों पर किया जाता है। असंगठित विनिर्माण हेतु संगठित तथा असंगठित विनिर्माण के उत्पादन का आधार वर्ष अनुपात इस्तेमाल किया जाता है। उपभोग के लिए कुल उपलब्ध आपूर्ति उत्पाद शुल्क, आयात शुल्क, व्यापार तथा परिवहन लाभ द्वारा परिकलित होती है। इसके पश्चात् सरकारी उपभोग, पूंजीगत निर्माण, निर्यात आपूर्ति में इस्तेमाल तालिका का प्रयोग करते हुए घटाई जाती है और शेष गैर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय होता है। <p>(ग) इलैक्ट्रीसिटी, गैस तथा अन्य ईंधन: आधार वर्ष के लिए इलैक्ट्रीसिटी की खपत एनएसएस के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से ली गई है; यह घरेलू उपभोग के लिए बेची गई इलैक्ट्रीसिटी के संबंध में सीईए द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के साथ आगे भेजा जाता है। प्राकृतिक गैस की घरेलू खपत भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस सांख्यिकीय से ली जाती है।</p> <p>(घ) सेवाएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> अधिकतर सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, होटल और रेस्टोरेंट) हेतु आधार वर्ष अनुमान उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से परिकलित किया जाता है और उसके बाद से सकल मूल्य वृद्धि के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। परिवहन: आधार वर्ष में यात्रियों से प्राप्त आय के लिए पीएफसीई का अनुपात पूरी श्रृंखला में स्थिर माना जाता है और उसके बाद पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों की वृद्धि का इस्तेमाल करते हुए बढ़ा जाता है। संचार तथा अन्य विभिन्न व्यक्तिगत सेवाएं: पीएफसीई कुल निपज का प्रतिशत निश्चित होता है। आवास, जलापूर्ति: जीवीए वृद्धि अनुमान आगे प्रयोग किए जाते हैं। <p>स्थिर कीमतों पर:</p> <p>(क) कृषि: अनुमान आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है।</p> <p>(ख) विनिर्माण: प्रमुख डब्ल्यूपीआई अपस्थापक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।</p> <p>(ग) इलैक्ट्रीसिटी, गैस तथा अन्य ईंधन: आधार वर्ष अनुमान मात्रा सूचकांक का इस्तेमाल करते हुए लगाए जाते हैं।</p>		

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	वर्तमान कीमतें: एल वी तथा स्वायत्त सस्थाओं के द्वारा सहित केन्द्र एवं राज्य बजट दस्तावेजों के यहाँ से वास्तविक अनुमान संशोधित अनुमान	(संशोधन विचार विमर्श पर आधारित होता है।)	
	वर्तमान कीमत: सीपीआई तथा डब्ल्यूपीआई आधारित संकेतकों का उपयोग करके निजी घटक कम किए जाते हैं।		
सकल नियत पूंजी निर्माण	<p>वर्तमान मूल्य:</p> <p>पूंजी निर्माण सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीई) का अनुमान परिसंपत्तियों के प्रकार द्वारा संस्थानागत क्षेत्र के प्रकार द्वारा और आद्योगिक इस्तेमाल द्वारा संकलित होता है। चार प्रकार की परिसंपत्तियां और इस्तेमाल की गई प्रणाली निम्न रूप में दी गई हैं:</p> <p>(क) आवास, अन्य भवन तथा संरचना (डीओबीएस): डीओबीएस के नए निर्माण के हिस्से का निपज जीएफसीएफ के रूप में लिया जाता है जिसका निर्माण क्षेत्र जीवीओ में उल्लेख किया गया है। संस्थान तथा उद्योगवार अनुमान के संकलन के लिए बजट दस्तावेजों, सार्वजनिक क्षेत्रों के निगमों की वार्षिक रिपोर्टों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, गैर सरकारी निगमों की वार्षिक रिपोर्टों और परिवारों के लिए एनएसएस सर्वेक्षण में दिए गए नए निर्माण के संबंध में व्यय का इस्तेमाल किया जाता है।</p> <p>(ख) मशीनरी और उपकरण (एम एंड ई): एम एंड ई परिसंपत्तियों का जीएफसीएफ अनुमान उत्पाद प्रवाह पहुंच का इस्तेमाल करते हुए संकलित किया जाता है। संस्थान तथा उद्योगवार अनुमान के संकलन के लिए बजट दस्तावेजों, सार्वजनिक क्षेत्रों के निगमों की वार्षिक रिपोर्टों, और परिवारों के लिए एनएसएस सर्वेक्षण में दिए गए एनएमई के संबंध में पूंजीगत व्यय का इस्तेमाल किया जाता है।</p> <p>(ग) कृषि संबंधी जैविक संसाधन (सीबीआर): पशुधन में वृद्धि तथा बागवानी कृषि के क्षेत्र की वृद्धि के संबंध में व्यय को सीबीआर संपत्ति के अंतर्गत पूंजी निर्माण के रूप में माना जाता है। पशुधन तथा बागवानी की जीएफसीएफ परिसंपत्ति के संकलन हेतु नाबार्ड रिपोर्ट से प्राप्त पशुधन गणना से प्राप्त पूंजीगत स्टॉक की सूचना और बागवानी कृषि के संबंध में व्यय का इस्तेमाल किया जाता है।</p> <p>(घ) बौद्धिक संपत्ति उत्पाद: बजट दस्तावेजों, सार्वजनिक क्षेत्रों के निगमों की वार्षिक रिपोर्टों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, गैर सरकारी निगमों की वार्षिक रिपोर्टों और परिवारों के लिए सॉफ्टवेयरों परिसंपत्ति आंकड़े हेतु एनएसएस का 67वां दौर तथा अनिगमित उपक्रमों से अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के बारे में कुल पूंजीगत व्यय का इस्तेमाल किया जाता है।</p> <p>स्थिर मूल्य:</p> <p>अनुमान उपयुक्त डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई आधारित अपस्फीतिकारकों का इस्तेमाल करते हुए संकलित किया जाता है।</p>		
वस्तुओं का निर्यात तथा सेवाएं	<p>वर्तमान मूल्य:</p> <p>वस्तुओं के निर्यात तथा सेवाओं का आंकड़ा आरबीआई से प्राप्त होता है।</p> <p>स्थिर मूल्य:</p> <p>वस्तुओं का निर्यात, निर्यात सूचकांक की इकाई के मूल्य द्वारा अपस्फीतिकारक होता है और सेवाओं का निर्यात सेवा क्षेत्र के निर्विवाद मूल्य सूचकांक द्वारा अपस्फीतिकारक होता है।</p>		

क्षेत्र	पहला संशोधित अनुमान	दूसरा संशोधित अनुमान	तीसरा संशोधित अनुमान
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	<p>वर्तमान कीमतें:</p> <p>एल बी तथा स्वायत्त संस्थाओं के डाटा सहित केन्द्र एवं राज्य बजट दस्तावेजों के संशोधित अनुमान।</p> <p>स्थिर कीमतें:</p> <p>सी पी आई तथा डब्ल्यूपी आई आधारित संकेतकों का उपयोग करके निजी घटक कम किए जाते हैं।</p>	<p>एल बी तथा स्वायत्त संस्थाओं के डाटा सहित केन्द्र एवं राज्य बजट दस्तावेजों से वास्तविक अनुमान</p>	<p>एल बी तथा स्वायत्त संस्थाओं के डाटा सहित केन्द्र एवं राज्य बजट दस्तावेज (संशोधन विचार विमर्श पर आधारित होता है।)</p>
<p>टिप्पणी:</p> <p>^ आगम का वन संबंधी क्षेत्र में वर्तमान मूल्य पर निपज के कुल मूल्य का 16.2 प्रतिशत तक माना जाता है।</p> <p># सीमेंट और सीमेंट उत्पाद, लोहा और इस्पात, ईट, टाइल्स, टिम्बर, बिटुमेन, कांच उत्पादों के उपभोग के लिए पण्य-प्रवाह उपागम को निर्दिष्ट करता है।</p> <p>* जीएसटी लागू करने के बाद बिक्री कर जीएसटी के अधीन अब शामिल कर दिया गया है और अब कुल बिक्री तुलनीय प्राक्कलन को अनुमानित किया जाता है।</p>			